



हिन्दी दैनिक

पथ प्रवाह

RNI No.: UTTHIN/2011/39282

हर खबर पर पैनी नजर



वर्ष:4 अंक:350 पृष्ठ:08 मूल्य:1 रुपये

pathpravah.com

हरिद्वार, बुधवार, 24 दिसंबर 2025

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के अल्मोड़ा दौरे में दिखाई दी सुशासन की झलक

पथ प्रवाह, अल्मोड़ा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार का संकल्प है कि प्रशासन सीधे गांव तक पहुंचे और आमजन को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें। इसी उद्देश्य के तहत 'प्रशासन गांव की ओर' अभियान को प्रभावी रूप से लागू किया गया है, जिसके सकारात्मक परिणाम जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहे हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह बात विकासखंड ताड़ीखेत की न्याय पंचायत जैनोली में आयोजित बहुउद्देशीय शिविर के दौरान जनता से कही, मुख्यमंत्री ने शिविर में लगाए गए सभी विभागीय स्टालों का निरीक्षण किया तथा मुख्यसेवक स्टॉल पर बैठकर ग्रामीणों की जनसमस्याएं गंभीरता से सुनीं।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने आमजन से सीधा संवाद करते हुए प्राप्त शिकायतों पर एक-एक कर चर्चा की और संबंधित विभागीय अधिकारियों को तत्काल एवं समयबद्ध समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन शिविरों का उद्देश्य केवल शिकायतें सुनना नहीं, बल्कि मौके पर समाधान सुनिश्चित करना है, ताकि शासन और जनता के बीच विश्वास और संवाद और अधिक मजबूत हो।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि सरकार



के सभी विभाग एक ही मंच पर जनता के द्वार पर उपस्थित हैं और आमजन को इस सुविधा का अधिकतम लाभ उठाना चाहिए। यह कार्यक्रम विशेष रूप से जनता की सुविधा और समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए आयोजित किए जा रहे हैं।

शिविर के दौरान पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज, जैनोली के जर्जर भवन को लेकर सामने आई शिकायत पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने विद्यालय भवन के जीर्णोद्धार की घोषणा की। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को सुरक्षित एवं बेहतर शैक्षणिक वातावरण

उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है और शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि 'प्रशासन गांव की ओर' अभियान शासन और जनता के बीच संवाद, विश्वास और सहभागिता को मजबूत करने की दिशा में एक प्रभावी पहल है, जिससे जनसमस्याओं का समाधान त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी रूप से किया जा रहा है। कार्यक्रम में रानीखेत विधायक प्रमोद नैलवाल, जिलाधिकारी अंशुल सिंह, मुख्य विकास अधिकारी रामजीशरण शर्मा, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट गौरी प्रभात सहित



प्रशासनिक अधिकारी और सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

प्रशासनिक की कार्यशैली से प्रसन्न दिखे मुख्यमंत्री

अल्मोड़ा के दो दिवसीय दौर पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से प्रशासनिक कार्यशैली का फीड बैक लिया। अल्मोड़ा की समस्याओं की बारीकी से जानकारी ली। केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का संजीदगी से अनुपालन होता देख सीएम धामी

बेहद प्रसन्न नजर आए। उन्होंने जिलाधिकारी अंशुल सिंह की कार्यशैली और जनता के प्रति संवेदनाओं के साथ किए जा रहे कार्यों की सराहना की।

सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के अल्मोड़ा भ्रमण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बेहद चाक चौबंद रही। चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहा। जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने मुख्यमंत्री के भ्रमण कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्थाओं पर नजर बनाकर रखी।

जनजातीय समाज की पहचान, सम्मान और आत्मनिर्भरता पर जोर: किरन रिजिजू

आईजीएनसीए में पुस्तक 'भारतीय जनजातीय समाज' का लोकार्पण



पथ प्रवाह, नई दिल्ली। केन्द्रीय संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि भारतीय जनजातीय समाज का देश के निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, लेकिन लंबे समय तक उन्हें वह सम्मान नहीं मिला, जिसके वे वास्तविक हकदार थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनजातीय समाज का सशक्तिकरण उसकी पहचान, संस्कृति और आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए ही संभव है, न कि उसकी मौलिक पहचान को कमजोर कर।

यह विचार उन्होंने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र (आईजीएनसीए) के जनपद सम्पदा विभाग द्वारा 'ज्ञानपथ शृंखला' के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में व्यक्त किए। इस अवसर पर समाजशास्त्री एवं शिक्षिका डॉ. स्वीटी तिवारी द्वारा लिखित पुस्तक 'भारतीय जनजातीय समाज (शिक्षित एवं सशक्त भूमिका में आत्मनिर्भरता की ओर)' का लोकार्पण किया गया।

कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य उपस्थित रहे, जबकि विशेष अतिथि आयोग की सदस्य डॉ. आशा लकड़ा रहीं। कार्यक्रम का स्वागत

वक्तव्य आईजीएनसीए जनपद सम्पदा विभाग के अध्यक्ष प्रो. के. अनिल कुमार ने दिया। इस अवसर पर वनवासी कल्याण आश्रम के सुरेश कुलकर्णी की भी गरिमामय उपस्थिति रही।

अपने संबोधन में किरण रिजिजू ने कहा कि सेवा के नाम पर यदि जनजातीय समाज की सांस्कृतिक पहचान को बदला जाता है, तो ऐसी सेवा का कोई अर्थ नहीं रह जाता। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनजातीय समुदायों के सशक्तिकरण हेतु किए गए प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि जनजातीय समाज से तीन मंत्रियों को मंत्रिमंडल में स्थान देना और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाना सम्मान का प्रतीक है।

पुस्तक की लेखिका डॉ. स्वीटी तिवारी ने जनजातीय समाज की ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक यात्रा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि शिक्षा केवल साक्षरता नहीं, बल्कि अधिकारों की समझ और आत्मनिर्भरता का माध्यम है।

यह कार्यक्रम विद्वानों, शोधार्थियों, विद्यार्थियों और संस्कृति-अध्ययन से जुड़े प्रबुद्धजनों की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ।

उत्तराखंड के रोहन सहगल को केरल चुनाव प्रभारी की कमान, भाजयुमो में खुशी का संचार

पथ प्रवाह, हरिद्वार/नई दिल्ली

भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आगामी केरल विधानसभा चुनावों को लेकर संगठनात्मक स्तर पर बड़ा निर्णय लेते हुए उत्तराखंड से राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रोहन सहगल को केरल चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। इस नियुक्ति को पार्टी के युवा नेतृत्व को सशक्त करने और दक्षिण भारत में भाजपा के संगठनात्मक विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। रोहन सहगल इससे पूर्व बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान जैसे प्रमुख राज्यों में चुनावों के दौरान सह-प्रभारी की भूमिका निभा चुके हैं। इन राज्यों में भाजपा की चुनावी सफलता में उनके योगदान को संगठन ने सराहा है। अब केरल जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य में उन्हें यह अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है, जहां वे चुनाव प्रबंधन, रणनीतिक योजना और युवा कार्यकर्ताओं की प्रभावी भागीदारी के माध्यम से पार्टी को नई मजबूती प्रदान करेंगे।

राष्ट्रीय व प्रदेश नेतृत्व के प्रति जताया आभार

अपनी नियुक्ति पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए रोहन सहगल ने भाजपा के राष्ट्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि संगठन ने उन पर जो विश्वास जताया है, वह उनके लिए सम्मान और प्रेरणा दोनों है।

एचआरडीए ने अवैध निर्माण व प्लॉटिंग पर बुलडोजर से किया प्रहार

पथ प्रवाह, हरिद्वार

हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण एवं अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध सघन अभियान जारी रखते हुए हरिद्वार एवं रुड़की क्षेत्र में सख्त कार्रवाई की गई। लक्सर रोड, हरिद्वार में सूरज सैनी द्वारा कटरपुर चौक से बहादुरपुर जट्ट को जाने वाले मार्ग पर लगभग 5-6 बीघा भूमि में की जा रही अवैध प्लॉटिंग को प्राधिकरण टीम द्वारा जेसीबी की सहायता से नियमानुसार ध्वस्त किया गया। इसी क्रम में रुड़की क्षेत्र में इशार द्वारा राजकीय जूनियर हाईस्कूल इकबालपुर कर्मेलपुर के सामने लगभग 40म30 फीट क्षेत्रफल में किए जा रहे अवैध



उन्होंने कहा कि मैं इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय महामंत्री एवं युवा मोर्चा प्रभारी सुनील बंसल का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही, भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या के निरंतर मार्गदर्शन और विश्वास के लिए मैं उनका विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ।

केरल में संगठन को नई गति देने का संकल्प

रोहन सहगल ने केरल में पार्टी की हालिया

प्रगति को और आगे बढ़ाने के लिए राज्य नेतृत्व के साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि केरल का युवा वर्ग प्रगतिशील सोच रखता है और भाजपा के विकास आधारित दृष्टिकोण को अपनाने के लिए तैयार है।

उन्होंने कहा कि मैं भाजपा केरल प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर के नेतृत्व में, भाजयुमो केरल प्रदेश अध्यक्ष गोकुल एवं पूरी प्रदेश टीम के साथ मिलकर कार्य करने को उत्सुक हूँ। हमारा लक्ष्य हर बूथ पर पार्टी की उपस्थिति को मजबूत करना और 'विकसित भारत' के संकल्प को केरल के हर घर तक पहुंचाना है।

रणनीतिक अधिदेश: तीन प्रमुख स्तंभ

केरल में चुनाव प्रभारी के रूप में रोहन सहगल की भूमिका तीन प्रमुख रणनीतिक स्तंभों पर आधारित होगी— जमीनी स्तर पर मजबूती: बूथ स्तर तक भाजयुमो कार्यकर्ताओं को सक्रिय व ऊर्जावान बनाना।

युवा संपर्क: केंद्र सरकार की योजनाओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को केरल के युवाओं तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना।

चुनावी रणनीति: डेटा-संचालित प्रचार, सुदृढ़ संगठनात्मक ढांचा और प्रभावी चुनाव प्रबंधन के माध्यम से ऐतिहासिक प्रदर्शन सुनिश्चित करना।



व्यवसायिक निर्माण पर प्राधिकरण की शाखा कार्यालय रुड़की की टीम द्वारा पुलिस बल की उपस्थिति में कार्रवाई करते हुए निर्माण को सील किया गया। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि बिना

स्वीकृति किए जा रहे निर्माण एवं प्लॉटिंग को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य में भी इस प्रकार की अवैध गतिविधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।



जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के सख्त निर्देश, किसी भी सूरत में न हो सरकारी भूमि पर अतिक्रमण

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने मंगलवार को डाम कोठी पर बैठक करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिये कि जनपद की सरकारी भूमि एवं परिसंपत्तियों पर किए अतिक्रमण को तत्काल हटाने की कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि जनपद हरिद्वार को स्वच्छ, सुंदर जनपद बनाने के लिए सफाई अभियान में और अधिक तेजी लायी जाए और उसमें जन सहभागिता बढ़ायी जाए। बैठक में उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश है कि सरकारी भूमि एवं परिसंपत्तियों पर किसी भी तरह से कोई अतिक्रमण न हो तथा किए गए अतिक्रमण के विरुद्ध तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जनपद को स्वच्छ, सुंदर जनपद बनाने के लिए चलाए जा रहे सफाई अभियान में सभी अधिकारी और तेजी लाए तथा अपने अपने क्षेत्रों में बेहतर ढंग से सफाई व्यवस्था पर और अधिक फोकस देने को कहा है ताकि जनपद को स्वच्छ, सुंदर जनपद बनाए जा सके।

सिंचाई विभाग को अतिक्रमण हटाने के निर्देश

बैठक में जिलाधिकारी ने सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश को निर्देश दिए हैं कि उनकी भूमि पर जो भी अतिक्रमण किया गया है, उस अतिक्रमण को चिन्हित करते हुए, संबंधितों को नोटिस निर्गत किया जाए। यदि वह अतिक्रमण नहीं हटाते हैं तो अतिक्रमण हटाने की त्वरित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें, इसमें यदि प्रशासन के सहयोग की आवश्यकता है तो



अवगत कराए। उन्होंने एसडीओ सिंचाई उत्तर प्रदेश को निर्देश दिए हैं कि उनकी भूमि पर जो भी गंदगी है उन क्षेत्रों में साफ सफाई का कार्य त्वरित गति से किया जाए। सिंचाई विभाग हरिद्वार को भी निर्देश दिए हैं कि वह भी अपनी भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए आवश्यक कार्यवाही तत्परता से करे एवं सभी क्षेत्रों में साफ सफाई करना भी सुनिश्चित करे, सफाई में किसी भी प्रकार की कोई शिथिलता नहीं बरती जानी चाहिए।

एनएचआई राजमार्ग से हटाए अतिक्रमण

बैठक में जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता एनएचआई को निर्देश दिए हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क किनारे जो भी अतिक्रमण किया गया है, उसको चिन्हित करते हुए उसे तत्काल हटाने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए, इसके साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग पर

साफ सफाई करने के भी निर्देश दिए गए।

कूड़ा निस्तारण के लिए बनाएं कार्य योजना

बैठक में जिलाधिकारी ने मुख्य नगर आयुक्त से कहा कि आगामी कुंभ मेले को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए कचरा प्रबन्धन के उचित निस्तारण हेतु बेहतर कार्य योजना तैयार करने को कहा इसके साथ ही नगर निगम क्षेत्रांतर्गत कहीं भी कूड़े के ढेर न हो उनके उचित निस्तारण की कार्यवाही त्वरित गति से की जाए। उन्होंने नगर निगम क्षेत्रांतर्गत किए गए अतिक्रमण को भी चिन्हित करते हुए नगर निगम की भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही तत्परता से की जाए साथ ही उन्होंने कहा कि सभी वार्डों में व्यापक सफाई अभियान चलाया जाए।

अपने अपने क्षेत्रों में अतिक्रमण चिन्हित कर हटाएं

जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी एवं नगर



मजिस्ट्रेट को निर्देश दिए हैं कि उनके क्षेत्रांतर्गत राजस्व भूमि पर कहीं अतिक्रमण किया गया है तो उसको चिन्हित करते हुए तत्काल हटाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि जनपद में चलाए जा रहे सफाई अभियान की निरंतर मॉनिटरिंग करते हुए सफाई अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए तथा अधिक से अधिक लोगों को अभियान से जोड़ने के लिए प्रेरित करें।

साफ कार्य का किया निरीक्षण

जिलाधिकारी, मुख्य नगर अधिकारी ने अमरापुर घाट एवं शंकराचार्य चौक क्षेत्रांतर्गत की जा रही सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग को निर्देश दिए हैं कि उनके

द्वारा जो भी राष्ट्रीय राजमार्ग पर सफाई का कार्य किए जा रहा है उसको बेहतर ढंग से किए जाए तथा शंकराचार्य चौक के आसपास सौंदर्यकरण करने के निर्देश दिए इसके साथ ही घाटों के किनारे किसी भी तरह से कोई अतिक्रमण न किया जाए।

बैठक में मौजूद रहे ये अधिकारी

बैठक में मुख्य नगर आयुक्त नगर निगम नंदन कुमार, उप जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार, नगर मजिस्ट्रेट कुशम चौहान, अधिशासी अभियंता एनएचआई अतुल शर्मा, प्रोजेक्ट मैनेजर एनएचआई संतोष साही, एसडीओ सिंचाई उत्तर प्रदेश भारत भूषण, सहायक अभियंता कृष्ण कुमार सैनी, सहायक अभियंता सिंचाई हरिद्वार विजय सिंह, उप राजस्व अधिकारी सिंचाई कुलदीप रावत आदि मौजूद रहे।

एक नजर

डीएम मयूर दीक्षित की सख्ती के बाद धरातल पर उतरे अधिकारी, हटाया अतिक्रमण



पथ प्रवाह, हरिद्वार। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के सख्त निर्देशों के बाद अतिक्रमण हटाने के लिए अधिकारी धरातल पर उतरे। नगर मजिस्ट्रेट कुशम चौहान के नेतृत्व में अलकनंदा घाट से सीसीआर के समीप शिव घाट तक सख्ती के साथ अतिक्रमण हटाया गया। बता दें मंगलवार सुबह जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने डामकोठी पर बैठक कर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिये थे। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के सख्त निर्देशों के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शुरू की गई। नगर मजिस्ट्रेट कुशम चौहान ने बताया कि उनके नेतृत्व में नगर निगम की टीम द्वारा अलकनंदा घाट से सीसीआर के समीप शिव घाट तक अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान घाट पर लगी अवैध दुकानों, रेहड़ियों, ठेलियों आदि को हटवाया गया। इस दौरान सामान भी जब्त किया गया। साथ ही अतिक्रमणकारियों को सख्त रूप से निर्देशित किया गया कि दुबारा अतिक्रमण न करें। यदि दुबारा अतिक्रमण किया गया तो भारी जुर्माना लगाए जाने की कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने मौके पर उपस्थित नगर निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि घाटों पर दुबारा अतिक्रमण ना हो तथा साथ ही घाटों पर साफ सफाई की व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा जाए।

कांग्रेस ने की वीआईपी का नाम सार्वजनिक करने की मांग, फूका पुतला

पथ प्रवाह, हरिद्वार। अकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी आरोपी का नाम सार्वजनिक करने की मांग को लेकर देर शाम उत्तरी हरिद्वार से सटे हरिपुर कला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर पुतला फूका गया। इस दौरान हत्यारों को फांसी दिये जाने की मांग की गई। आरोप लगाया कि सरकार आरोपी को बचाने का प्रयास कर रही है। ग्राम प्रधान सविता शर्मा और अन्य लोगों की मौजूदगी में देर शाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यह प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार इस प्रकरण में प्रभावशाली वीआईपी नेता को बचाने का प्रयास कर रही है। कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हुई है। भाजपा पर आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा या सेवानिवृत्त न्यायाधीश की देखरेख में सीबीआई द्वारा कराई जाने की मांग की गई। कांग्रेस नेताओं ने सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो का हवाला दिया। प्रदर्शन करने वालों में अकित बहुखंडी, आशीष भट्ट, अकित बिजलवान, सीमा कोठारी, संजय रावत, विक्रान्त भारद्वाज, नितिन पांडे, सूरज सुंदरियल, अनीता शर्मा, नीतू बर्थवाल, नरेंद्र प्रसाद, भानु प्रताप, प्रीतम सिंह, दीपक सिंह, भारत लखेड़ा, रघुबीर सिंह, धर्मेन्द्र सिंह, हिमांशु, नीरज रावत, आकाश आदि मौजूद रहे।



पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने लगाया आरोप, बोले उर्मिला कर रही उनकी छवि धूमिल

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

भाजपा से निष्कासित ज्वालापुर के पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने वायरल हो रहे एक कथित ऑडियो क्लिप पर कड़ा रुख अपनाते हुए अपना पक्ष मीडिया के सामने रखा। उन्होंने इसे अपनी छवि धूमिल करने की साजिश करार दिया है। मंगलवार को हरिद्वार प्रेसक्लब में प्रेस वार्ता कर उन्होंने उर्मिला सनावर पर गंभीर आरोप लगाए और ज्वालापुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर दी।

प्रेस वार्ता के दौरान सुरेश राठौर ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर जो ऑडियो वायरल हो रहा है, उसमें उनकी आवाज नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) तकनीक का सहारा लेकर उनकी आवाज को कॉपी किया गया है, ताकि उनकी राजनीतिक और सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया जा सके। आरोप लगाते हुए कहा कि उर्मिला सनावर जानबूझकर उन्हें बदनाम करने के लिए अनर्गल आरोप लगा रही हैं। उन्होंने ज्वालापुर पुलिस को तहरीर सौंपकर मांग की है कि इस फर्जी ऑडियो की साइबर जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त मुकदमा दर्ज हो। पूर्व विधायक ने इसे एक



गहरा राजनीतिक षड्यंत्र बताते हुए कहा कि सत्य जल्द ही सबके सामने आएगा। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से उर्मिला सनावर और सुरेश राठौर के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। उर्मिला द्वारा कुछ गंभीर दावे किए जाने के बाद एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई थी, जिसे आधार बनाकर राठौर को घेरा जा रहा था। सुरेश राठौर का कहना है कि उसके उर्मिला से कोई संबंध नहीं है, वह केवल उनकी छवि धूमिल करने के लिए यह सब कर रही है। प्रेसक्लब में अपना पक्ष रखते हुए पूर्व

विधायक सुरेश राठौर ने कहा कि वायरल किया गया ऑडियो पूरी तरह से छेड़छाड़ किया हुआ है और इसे जानबूझकर उनकी राजनीतिक और सामाजिक छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से फैलाया गया है। उन्होंने मांग की कि पुलिस संबंधित मोबाइल फोन को कब्जे में लेकर उसकी तकनीकी और फोरेंसिक जांच कराए, ताकि सच्चाई सामने आ सके। उन्होंने आरोप लगाया कि उर्मिला सनावर द्वारा उनके नाम का गलत उपयोग किया जा रहा है और पूरे प्रदेश में इस मामले को सनसनीखेज बनाकर फैलाया गया है। पूर्व विधायक ने कहा कि यह पूरा मामला एक सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य उन्हें बदनाम करना और उनके परिवार को तोड़ना है। उन्होंने आरती गौड़ को अपनी बेटी बताया। राठौर ने कहा कि उर्मिला सनावर उनके परिवार पर व्यक्तिगत आरोप लगाकर मानसिक उत्पीड़न कर रही है और उनकी पत्नी को पाकिस्तानी बताने जैसे गंभीर और निराधार आरोप लगा रही है, जबकि उनकी पत्नी का जन्म हरिद्वार में ही हुआ है। पूर्व विधायक ने स्पष्ट कहा कि यदि उर्मिला सनावर यह दावा कर रही हैं कि उनसे शादी हुई है, तो वह इसके ठोस और वैधानिक प्रमाण सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत करें।

सलेमपुर में अवैध खनन कर रही 2 जेसीबी और 2 ट्रैक्टर ट्रॉली सीज

पथ प्रवाह, हरिद्वार। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर की गई कार्रवाई से अवैध खनन करने वालों में हड़कंप मचा है। राजस्व विभाग की टीम ने सलेमपुर में अवैध खनन कर रही दो जेसीबी और दो ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़कर सीज किये हैं। बता दें सरकार को राजस्व की हानि पहुंचाने वालों के विरुद्ध जिलाधिकारी मयूर दीक्षित सख्ती से कार्यवाही कर रहे हैं।

जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सभी उप जिलाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में कड़ी निगरानी रखते हुए अवैध खनन करने वाले के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।

इसी क्रम में उप जिलाधिकारी हरिद्वार जितेंद्र कुमार ने अवगत कराया है कि सलेमपुर तथा पूरनपुर, साल्हापुर में अवैध खनन के



सूचना पर उनके निर्देशन में तहसीलदार सचिन कुमार के नेतृत्व में टीम का गठन करते हुए, तहसील की टीम मौके पर पहुंची। टीम को 2

जेसीबी तथा 2 ट्रैक्टर ट्रॉली अवैध खनन करते हुए पाए गए, जिन्हें सीज कर सुमन नगर चौकी के सुपुर्द किया गया।



लैब टैक्नीशियन की हत्या का 11 महीने बाद सनसनीखेज खुलासा, होमगार्ड निकला हत्यारा

पथ प्रवाह, हरिद्वार। बीती जनवरी माह में हुई लैब टैक्नीशियन की गोली मारकर की गयी हत्या की गुत्थी को रानीपुर कोतवाली पुलिस ने सुलझा लिया है। घटना का सनसनीखेज खुलासा करते हुए पुलिस ने एक होमगार्ड को गिरफ्तार किया है। जिसने हत्या की बात पुलिस के सामने कबूल की है। रानीपुर कोतवाली में प्रेसवार्ता के दौरान घटना का खुलासा करते हुए एसएसपी प्रमोद सिंह डोभाल ने बताया कि कोतवाली रानीपुर क्षेत्र में 18 जनवरी को ग्राम गढ़मीरपुर में लैब टैक्नीशियन वसीम की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

इस सम्बन्ध में मृतक के पिता मुस्तकीम की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। बताया कि घटना के खुलासे के लिए पुलिस टीमों ने घटनास्थल के आसपास लगे विभिन्न सीसीटीवी कैमरों का अध्ययन, मृतक के मोबाइल नंबर की डिजिटल साक्ष्यों का विश्लेषण सहित अनेक प्रयास किए गए, किन्तु प्रारम्भिक स्तर पर कोई ठोस सुराग प्राप्त नहीं हो सका। जांच के दौरान एक ग्रे रंग की स्कूटी संख्या यूके 08 एक्वू 2050 संदिग्ध के रूप में सामने आयी। स्कूटी की तलाश के दौरान 22 दिसम्बर की रात्रि में रेयूलेटर



पुलिस सुमननगर से चैकिंग के दौरान पुलिस टीम ने एक व्यक्ति को स्कूटी सहित हिरासत में लिया। हिरासत में लिए गए व्यक्ति ने नाम पता अभिमन्यु पुत्र अर्जुन सिंह, निवासी ग्राम सकौती, पोस्ट गुरुकुल नारसन, थाना मंगलौर, जनपद हरिद्वार, उम्र 32 वर्ष बताया।

महिला मित्र को कर रहा था परेशान

हिरासत में लिए गए संदिग्ध ने पूछताछ में

बताया कि वह वर्ष 2015 में होमगार्ड में भर्ती हुआ था। वर्ष 2024 में उसकी दोस्ती होमगार्ड महिला से हुई। महिला की पूर्व में मृतक वसीम से दोस्ती थी तथा उसके मोबाइल में वसीम के साथ फोटो एवं मैसेज मौजूद थे। मृतक महिला को लगातार कॉल व मैसेज कर परेशान व प्रताड़ित किए जाने से व्यक्ति के मन में आक्रोश उत्पन्न हुआ और उसने वसीम को रास्ते से हटाने की योजना बनाई।



सोशल मीडिया का सहारा लेकर पहुंचा वसीम तक

आरोपी ने सोशल मीडिया के माध्यम से वसीम की जानकारी एकत्रित की तथा उसकी दिनचर्या की रेकी की। 17 जनवरी 25 की सायं, आरोपी ने महिला की स्कूटी को चौकी बाजार बहादुराबाद से दूसरी चाबी द्वारा खोलकर मृतक की मोटरसाइकिल का पीछा किया। ग्राम गढ़ के पास अवसर पाकर आरोपी ने चलती मोटरसाइकिल पर वसीम को देशी तमंचे से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त स्कूटी को कब्जे में ले लिया। आरोपी की निशादेही पर धनौरी तेलीवाला रोड, करवला स्थित जंगल से घटना में प्रयुक्त तमंचा व जिन्दा कारतूस बरामद किया। पुलिस ने विधिक कार्यवाही करते हुए आरोपित का चालान कर दिया है।

एक नजर

हरिद्वार पुलिस की गिरफ्त में आए दो शातिर मोबाइल स्नैचर



पथ प्रवाह, हरिद्वार। हरिद्वार पुलिस ने मोबाइल छीनकर भागने वाले दो शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। उनके पास छीना गया मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। पुलिस इनके अपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी जुटा रहा है। पुलिस के मुताबिक 22 दिसंबर को शिवम वर्मा पुत्र संतोष कुमार निवासी पन्थी सेरामऊ दक्षिणी सदर बाजार जिला शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश हाल पता रोशनाबाद थाना सिडकुल जनपद हरिद्वार ने दिनांक 05/11/25 को कालागेट रोशनाबाद सिडकुल के पास से दो अज्ञात मोटरसाइकिल सवार द्वारा उसका वीवो झू-4 फोन छीनकर भाग जाने के संबंध में थाना सिडकुल पर प्रभावी धाराओं में अभियोग दर्ज किया गया था। जिसपर कार्यवाही करते हुए थाना सिडकुल पुलिस द्वारा महिंद्रा ग्राउंड के किनारे झाड़ियों के पास से दो संदिग्धों को दबोच कर छीना गया मोबाइल बरामद की गई। गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम मोहम्मद फैज पुत्र शरीफ निवासी रोशनाबाद और तोहिद पुत्र सुल्तान निवासी रोशनाबाद निकट झंडा चौक थाना सिडकुल है।

सिडकुल में अवैध तमंचे के साथ एक गिरफ्तार



पथ प्रवाह, हरिद्वार। थाना सिडकुल पुलिस द्वारा चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के तहत एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा 315 बोर, दो जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद किया है। थानाध्यक्ष सिडकुल के मुताबिक देर रात थाना सिडकुल क्षेत्र में पुलिस की टीम संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान उप निरीक्षक इंद्रजीत सिंह राणा अपनी टीम के साथ गश्त कर रहे थे। चेकिंग के दौरान श्री राम महाकाल प्रॉपर्टीज के सीमेंट गोदाम के पीछे से एक संदिग्ध युवक को पकड़ा गया। पूछताछ में उसने अपना नाम सन्नी बताया। पुलिस टीम द्वारा तलाशी लेने पर उसके पास से एक अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद हुए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार विधिक कार्यवाई की।

हरिद्वार में 21 जनवरी से होगा ई-रिक्शाओं का भौतिक सत्यापन, इससे पहले पुलिस वैरिफिकेशन जरूरी

पथ प्रवाह, हरिद्वार। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), हरिद्वार के कार्यालय में मंगलवार को ई-रिक्शा संचालन से संबंधित विषयों को लेकर बैठक की गई। बैठक में नवोदय चौक, रानीपुर मोड़, बहादुराबाद एवं लक्सर रोड क्षेत्र के ई-रिक्शा यूनियन के प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। बैठक की अध्यक्षता सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), हरिद्वार निखिल शर्मा द्वारा की गई। बैठक में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), हरिद्वार नेहा झा तथा वरुणा सैनी, परिवहन कर अधिकारी (इंटरसेक्टर) भी उपस्थित रहें। बैठक के दौरान ई-रिक्शा के सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं नियमबद्ध संचालन के संबंध में जिला प्रशासन एवं जिला सड़क सुरक्षा समिति द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के प्रावधानों की जानकारी यूनियन प्रतिनिधियों को दी गई। अधिकारियों द्वारा बताया गया कि SOP के अंतर्गत दिनांक 21.12.2025 से 20.01.2026 तक एक माह की अवधि में सभी ई-रिक्शा वाहन स्वामियों एवं चालकों को अपना पुलिस सत्यापन अनिवार्य रूप से पूर्ण कराना होगा। यदि कोई चालक अन्य जनपद अथवा अन्य राज्य का निवासी है, तो उसे संबंधित क्षेत्र एवं हरिद्वार जनपद-दोनों स्थानों से पुलिस सत्यापन कराना आवश्यक होगा।

पुलिस सत्यापन के बाद ही होगा भौतिक सत्यापन

पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण होने के



पश्चात दिनांक 21.01.2026 से 20.02.2026 के मध्य ई-रिक्शा वाहनों के दस्तावेजों की जांच एवं वाहनों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। इस अवधि में ई-रिक्शा वाहन स्वामियों/चालकों को चरणबद्ध तरीके से कार्यालय में बुलाया जाएगा, जहां वाहन एवं संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे।

अधिकारियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि निर्धारित अवधि के उपरांत जिन ई-रिक्शा वाहनों का पुलिस सत्यापन, दस्तावेज सत्यापन एवं भौतिक निरीक्षण पूर्ण नहीं होगा, उन्हें मार्ग पर संचालन की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। SOP का उद्देश्य शहर में यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना, सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना है।

यूनियन प्रतिनिधियों ने सामने रखी समस्याएं

बैठक के दौरान यूनियन प्रतिनिधियों द्वारा रखी गई समस्याओं एवं सुझावों को भी गंभीरता से सुना गया तथा अधिकारियों द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि नियमों के दायरे में रहते हुए व्यवहारिक समस्याओं के समाधान पर विचार किया जाएगा। साथ ही यूनियन प्रतिनिधियों से अपेक्षा की गई कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में सभी ई-रिक्शा चालकों एवं वाहन स्वामियों को SOP की जानकारी दें तथा निर्धारित समयसीमा के भीतर सभी औपचारिकताएँ पूर्ण कराएं। अधिकारियों ने कहा कि नियमों का पालन करने वाले ई-रिक्शा चालकों को किसी प्रकार की अनावश्यक असुविधा नहीं होने दी जाएगी, जबकि नियमों की अवहेलना की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

धूम सिंह मेमोरियल पब्लिक स्कूल के अथर्व चौहान ने रचा इतिहास

68वीं नेशनल शूटिंग प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन, इंडिया टीम ट्रायल के लिए क्वालीफाई

पथ प्रवाह, हरिद्वार

धूम सिंह मेमोरियल पब्लिक स्कूल, ज्वालापुर के छात्र अथर्व चौहान (कक्षा ढुड़) ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है। अथर्व ने 18 दिसंबर 2025 को भोपाल में आयोजित 68वीं नेशनल शूटिंग प्रतियोगिता में प्रतिभाग करते हुए 601 अंक अर्जित किए और 580 के क्वालीफाइंग स्कोर को पार कर इंडिया टीम ट्रायल के लिए क्वालीफाई किया है। अब अथर्व आगामी एक माह बाद दिल्ली में आयोजित होने वाले इंडिया टीम ट्रायल में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे।

कम उम्र में राष्ट्रीय मंच पर यह उपलब्धि अथर्व की कड़ी मेहनत, अनुशासन और लक्ष्य के प्रति समर्पण को दर्शाती है। इस सफलता के पीछे उनके कोच योगेंद्र यादव (देवभूमि शूटिंग ट्रेनिंग एकेडमी) का कुशल मार्गदर्शन और



सतत प्रशिक्षण अहम भूमिका में रहा, जिनके निर्देशन में अथर्व ने अपनी तकनीक और आत्मविश्वास को मजबूत किया।

विद्यालय परिवार ने इस उपलब्धि पर गर्व

व्यक्त करते हुए अथर्व को हार्दिक बधाई दी है। विद्यालय के डायरेक्टर मुकुल चौहान ने कहा कि अथर्व की यह उपलब्धि हम सभी के लिए गर्व का विषय है। उनकी प्रतिभा और समर्पण प्रशंसनीय है। यह सफलता साबित करती है कि निरंतर मेहनत और दृढ़ संकल्प से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। हमें पूर्ण विश्वास है कि अथर्व भविष्य में और भी ऊँचाईयाँ छूकर देश का नाम रोशन करेंगे।

प्रिंसिपल श्रीमती साधना भाटिया ने कहा कि अथर्व की इस शानदार सफलता ने विद्यालय के प्रत्येक सदस्य को प्रेरित किया है। यह उपलब्धि दर्शाती है कि जब विद्यार्थी अपने सपनों के पीछे पूरी लगन से चलते हैं, तो सफलता अवश्य मिलती है। विद्यालय अथर्व के हर कदम पर उनके साथ खड़ा है और हम सभी मिलकर भविष्य के चैंपियंस तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

संपादकीय

गांव तक सरकार, भरोसे तक शासन

‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ अभियान केवल एक प्रशासनिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि उत्तराखंड में सुशासन की उस सोच का सशक्त प्रमाण है, जिसमें सरकार खुद जनता के द्वार तक पहुँचती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में शुरू हुई यह पहल क्योंकि पंचायत स्तर पर शासन और नागरिक के बीच की दूरी को खत्म करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बनकर उभरी है।

एक ही सप्ताह में 93 बहुदृश्याय शिविरों के माध्यम से हजारों शिकायतों का निस्तारण और लगभग तीस हजार ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ मिलना इस बात का संकेत है कि यदि प्रशासन इच्छाशक्ति के साथ मैदान में उतरे, तो व्यवस्था बेझुन नहीं बल्कि समाधान बन जाती है। प्रमाणपत्रों का मौके पर निर्गमन और समरस्या का त्वरित समाधान उस पारदर्शिता को दर्शाता है, जिसकी अपेक्षा आमजन वर्षों से करता रहा है।

मुख्यमंत्री का स्वयं शिविरों में पहुँचना, ग्रामीणों से सीधा संवाद करना और अधिकारियों को समयबद्ध निस्तारण के निर्देश देना इस अभियान को औपचारिकता से ऊपर उठाकर संवेदनशील प्रशासन का स्वरूप देता है। यह संदेश स्पष्ट है कि अब शासन केवल फाइलों में नहीं, बल्कि गांव की चौपाल और न्याय पंचायत तक सक्रिय है।

17 दिसंबर से प्रारंभ यह अभियान डेढ़ माह तक चलना प्रस्तावित है, जो यह दर्शाता है कि सरकार इसे तात्कालिक पहल नहीं, बल्कि स्थायी प्रशासनिक संस्कृति बनाना चाहती है। मंत्रीगणों और वरिष्ठ अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी यह सुनिश्चित करती है कि योजनाओं का लाभ कागजों से निकलकर वास्तविक लाभार्थियों तक पहुँचे।

वास्तव में, 'जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार' लोकतंत्र के उस मूल भाव को मजबूत करता है, जहां सरकार जनता की सेवा में खड़ी दिखती है—न कि जनता सरकार के दरवाजों पर। यही सुशासन की असली पहचान है।

स्मार्टफोन वाली दुनिया में स्मार्ट उपभोक्ता बनने की दरकार

दिलीप कुमार पाठक

हमेशा सही कार्य करें, भले ही वह लोकप्रिय न हो; समय आपके मूल्य को समझा देगा और आपके ग्राहक आप पर भरोसा करेंगे
- रतन टाटा

आज का दौर विशुद्ध बाजारवादी है, यूरोप व अमेरिका बाजारवादी अवधारणा को पोषित करने वाली शक्तियों के रूप विख्यात हैं, पूरे विश्व के बाजार पर जिसका अधिक प्रभुत्व है वह आज अधिक शक्तिशाली है। भारत भी एक प्रमुख शक्ति बनने के मुहाने पर खड़ा है, परंतु यहां उपभोक्ता अधिकारों की समझ-पूँर्णतः विकसित नहीं है, सामान्य उपभोक्ता कई बार बाजार की चालाकियाँ समझ नहीं पाता है। बाजार में उपभोक्ता के तौर पर वह कई बार ठगा जाता है लेकिन उसका कोई भी हल उसके पास नहीं रहता। भारत में सामाजिक, शैक्षणिक स्थितियाँ अभी यूरोप व अमेरिकी देशों जैसी नहीं हैं। यहाँ का सामान्य उपभोक्ता बहुत जागरूक नहीं तो अशिक्षित उपभोक्ता के जागरूक होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यह एक ऐसा विषय है जिसके बारे में जागरूकता का अभाव दिखाई देता है। लेकिन जब बाजार उपभोक्ताओं के साथ कुछ गड़बड़ी होती है तो उनका असंतोष नज़र आता है।

भारत में कई उत्पादों पर (आई. एस. आई, एफ. एस. एस एआई) एगमार्क या हॉलमार्क जैसे निशान होते हैं, जो उनकी गुणवत्ता की गारंटी देते हैं। अगर किसी उत्पाद पर ये निशान नहीं हैं, तो इसका मतलब है उसकी गुणवत्ता पर भरोसा नहीं किया जा सकता। टीवी पर जागो ग्राहक जागो जैसे प्रचार भी उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए दिखाए जाते हैं। अलग-अलग उत्पादों के लिए अलग-अलग मानक बनाए गए हैं। इसके अलावा, लीगल मेट्रोलॉजी अधिनियम 2009 और उपभोक्ता कल्याण कोश जैसी पहल भी उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए हैं। भारत में शैक्षणिक स्थितियाँ अभी बहुत बेहतर नहीं हैं। एक बड़ा वर्ग केवल साक्षर है, उसके पास नागरिक अधिकारों की समझ नहीं है। वर्तमान तकनीक का दौर है। यह बड़ी तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है। टेक्नोलॉजी आज सहज रूप में उपलब्ध है। वह वित्तीय लेन-देन के लिए बहुत आसानी से उपयोग किया जाता है, सवाल वही है क्या जागरूकता है?

कम पढ़े-लिखे लोग अक्सर ठगे जाते

हैं, लेकिन अभी तक इसके लिए मजबूत नियम नहीं हैं, अगर नियम हैं तो कहीं-कहीं पालन नहीं है या समय के साथ उपभोक्ता के तौर-तरीकों में आए बदलावों को ध्यान में रखते हुए साक्षर-निरक्षर, जागरूक-गैरजागरूक का फर्क मिटाते हुए उनके हितों के लिए अभी कार्य किया जाना शेष है। जागरूक व्यक्ति तो आज अनेक अधिकारों को जान रहा है, उस तरह व्यवहार कर रहा है लेकिन जो जागरूक नहीं है उसे और अधिक जागरूक करने की आवश्यकता है।

यही कारण है कि भारत सरकार ने 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस घोषित किया है, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति ने उसी दिन ऐतिहासिक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधिनियम को स्वीकारा था। यह दिन भारतीय ग्राहक आन्दोलन के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। भारत में यह दिवस पहली बार वर्ष 2000 में मनाया गया। और प्रत्येक वर्ष मनाया जाने लगा है।

आज प्रत्येक व्यक्ति एक उपभोक्ता है, चाहे उसका व्यवसाय, आयु, लिंग, समुदाय तथा धार्मिक विचारधारा कोई भी हो। उपभोक्ता अधिकार और कल्याण आज प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का अविभाज्य हिस्सा बन गया है और हमने अपनी दैनिक जीवन में इस सभी का कभी न कहीं उपयोग किया है। प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। यह अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ. केनेडी द्वारा की गई एक ऐतिहासिक घोषणा में बताया गया था, जिसमें चार मूलभूत अधिकार बताए गए हैं। सुरक्षा का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार, चुनने का अधिकार, सुने जाने का अधिकार, इस घोषणा से अंततः यह तथ्य अंतरराष्ट्रीय रूप से मान्य हुआ कि सभी नागरिक, चाहे उनकी आय या सामाजिक स्थिति कोई भी हो उन्हें उपभोक्त के रूप में मूलभूत अधिकार हैं। 9 अप्रैल 1985 एक अन्त्युल्लेखनीय दिवस है, जब संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा उपभोक्ता संरक्षण के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों का एक सैट अपनाया गया और संयुक्त राष्ट्र की महासचिव को नीति में बदलाव या कानून द्वारा इन मार्गदर्शी सिद्धांतों को अपनाने के लिए सदस्य देशों से बातचीत करने का अधिकार दिया गया।

संवाद

महात्मा गांधीजी का अपमान और फिर परमाणु प्लांट का सच

संजय गोस्वामी

महात्मा गांधी नरेगा का विजन देश भर के ग्रामीण परिवारों को कम से कम 100 दिन की गारंटी वाला रोजगार देकर उनकी रोजी-रोटी की सुरक्षा को बढ़ाना था लेकिन जी राम जी के बाद उनका नाम हटा देना मुझे रूला दिया इसलिए मैं लिख पा रहा हूँ क्योंकि उनका आदर्श को भरी संसद जो देश का प्रतिनिधित्व करता है वहाँ फिर उनके विचारों को सूली पर लटकवा दि गई क्या भगवान राम ने ऐ कभी कहा उनका नाम बदलकर मेरा नाम राम की जगह जी राम जी कह दो और फ़िल्म स्टार कर्कना राणावत ने नया जमाना कह कर और भी अपमान किया पहले महात्मा गाँधी को समझते हैं उन्होंने नील की खेती पर चम्पारण में गए और किसानों की गुलामी लो आंदोलन में नया मोड़ देकर उन्होंने एक क्रांति ला दि थी इसी टॉपिक2017 में पर मेरा शोधपत्र भोपाल के एमपीएसएसआर में वाचन के लिए बुलाया गया तब मुझे गाँधी जी के बारे में एक से एक विद्वान ने अपने विचार रख कर उनका सम्मान किया इसी पर गाँधी अध्ययन समिति और महात्मा गाँधी अंतराष्ट्रीय विश्वविद्यालय द्वारा वर्धा में आयोजित एक राष्ट्रीय अधिवेशन पर गाँधीजी के बारे में मौका मिला और वहाँ के प्रोफेसर ने गाँधीजी पर कई शोध पत्र पर वाचन दिए अतः गाँधीजी का नाम बदलने से पहले बहुत ही शांत दिमाग से सोचा जाता है गाँधीजी ने स्वदेशी चीजों का बढ़ाया था और अगर देश उसी रहा पर चलता तो शायद विदेश कर्ज नहीं होता और देश के लोग खुश रहते, ऐ एक गंभीर मुद्दा इसलिए है कि एक भरी सदन में किसी योजना से नाम ही निकाल दिया गया और ऐ एक शर्मनाक घटना है क्योंकि गाँधीजी कोई मुगल शासक या गलत विचारों से नहीं थे तो सवाल ऐ उठता है फिर नाम ही मिटा दिया गया और भी इतनी बड़ी योजना से हटाना ही था तो गली चौराहा का नाम में परिवर्तन कर देते लेकिन एक भड़ी संसद में इस तरह की घटिया हरकत करने की आवश्यकता ही क्या थी और कैसे संसद से पास भी हो गया ऐ भी हैरान करने वाली है आज आप जो एपस्टीन फ्राइल अमेरिका का देख रहें हैं बिलकुल मत देखिए क्योंकि गाँधी ने सिखाया है बुरा मत देखो बुरा मत सोचो और बुरा मत करो ऐ उस समय का गाँधी था जो ब्रिटिश के बनाए हुए कपड़ो पर लाल मार कर अपनी चरखी पर बनाई हुई धागो से बस्त्र बनाया भी और वही पहना भी इसलिए देश में उन्हें राष्ट्रपिता कहते हैं पहले उनको समझो तब टिप्पणी करना और उसके लिए महात्मा गाँधी अंतराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के यहाँ जाकर देखिए या साबरमती आश्रम अहमदाबाद में देख लीजियेगा वहाँ जहाँ पानी पीते भी थे वहाँ वो कुर्वाँ आज भी मौजूद है पहले उनके आश्रम में जाकर देखें और किसी भी राष्ट्रवादी पार्टी ने गाँधीजी के नाम से खिलवाव नहीं किया था और भड़ी संसद में ऐ हो गया मैं मानता हूँ कांग्रेस ने देश की आजादी के बाद गलती किए होंगे लेकिन ऐ कतई नहीं

मान सकता की यदि उनका नाम है तो किस उद्देश्य से हटया गया ऐ संसद में हुआ इसलिए विदेशों में ऐ बात पहुंची होगी और देश शर्मसार हुआ है इसमें कोई दो राय नहीं है हिंदुस्तान का विभाजन के लिए गांधीजी जिम्मेदार नहीं थे ऐ जिन्ना और अंग्रेजी हुकूमत की मिलीभगत चाल थी और जहाँ तक हिन्दू मुसलमान की बात है वो अगर टूटता तो देश के अंदर कितनी आग फैलती जरा इसका भी अंदाजा लगाइये देश जब बंटवारा में ही जल रहा था तो ऐ भारत में हिन्दू मुसलमान होता तो और भी धर्म लोग थे सब बंट जाते और देश कमजोर होता और बाद में आपस में ही लड़ते रहते, इसलिए पहले उनके बारे में समझने की कोशिश करें और तब लगता है ऐ देश के लिए ठीक नहीं है तो चुनाव में ऐ मुद्दा आना चाहिए की मनरेगा की जगह जी राम जी रखनेवाला नई अगर जनता जीता देती तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को मैं सहृदय स्वीकार करता मीडिया में गांधी जी पर खूब बोलो और हमें याद आती है की स्वच्छ भारत में गांधी जी की खूब प्रचार होती है क्योंकि वो स्वच्छता पर बहुत ध्यान देते थे लेकिन जब उनका नाम और चीज से हटता तो चुनाव में इसके परिणाम एक अलग ही होता गांधीजी से एक और सबक लेना चाहिए ऐ जो शांति बिल है क्या देश के भले के लिए है गांधी जी स्वदेशी की बात करते थे तो परमाणु सयन्त्र जैसे संवेदनशिल मुद्दे को विदेशों के लिए क्यों भारत में खोला गया और इससे अपने वैज्ञानिकों से भरोसा उठेगा और जिन्होंने 1998 में सीटीवीटी बैन के बाद भी परीक्षण कर लिए और चीन और पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश गया जो बार बार हमारे सैनिकों को मार डालता था वह पाकिस्तान ने हरबाराहट में भारत की देखा देखी चीन से परमाणु सामग्री ली और बिस्फोट किया जो फुस जैसा था उसके बाद वहाँ उस समय रेडीएशन फैला था उस पर भी नजर डाल ले और उसी के बाद चीन ने उसपर इसके लिए इतना कर्ज डाल दिया की वो अभी तक उबर ही नहीं पाया लेकिन भारत में जो परमाणु परीक्षण किये थे वो एटम बम से भी ज्यादा शक्तिशाली हाइड्रोजन बम था और जो सूर्य की क्रिया के अनुसार था इसलिए वहाँ रेडीएशन नहीं फैला था और बाद में अटलजी ने 11 मई को हर साल नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाने का एलान किया और उन्होंने ही एक बार भड़ी सदन में कहा था पटी आणी, जाणी सत्ता आणी सत्ता जाणी पालेन इस देश का संविधान रहना चाहिए इसलिए जब कोई संविधान बन जाते हैं तो उसमें संसोधन करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए शांति बिल पास तो कर दिया लेकिन क्या इस क्षेत्र में जो लक्ष्य है वो हासिल होगी इसकी सम्भावना हमें दूर दूर तक नहीं दिखाई देती क्योंकि ऐ क्षेत्र ऐसा है कि इसमें काफी सावधानी और सुरक्षा अहम होता है और अभी भी ऐ शोध का विषय है अगर नहीं पता तो फ्रांस में इतर यानी प्यूजन रियेक्टर के बारे में जाने और सभी तक सफलता हासिल नहीं हुई है नाभिकीय क्षेत्र अन्य क्षेत्र से अलग है जैसे हम इसके खोज के बारे में चर्चा करें तो

1942 की दोपहर को, शिकागो यूनिवर्सिटी के स्टेन फील्ड के स्टैंड के नीचे एक स्ववैश कोर्ट में बने एक बहुत बड़े टेंट के अंदर एटॉमिक युग की शुरुआत हुई। वहाँ, इटैलियन वैज्ञानिक एनरिको फर्मी की देखरेख में, पहली कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन चेन रिएक्शन को तैयार किया गया। यानी 17 और 18वीं शताब्दी की खोज नहीं है एक तरह से मात्र 19वीं सदी का ही खोज है और भारत ने पहला परमाणु रिएक्टर अफ़सरा भारत में वैज्ञानिक भाभा ने पहला परमाणु रिएक्टर का निर्माण वर्ष 1956 में हुआ था। यह एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर भी था। जो मुंबई के ट्रॉम्बे में स्थित है यानि विश्व में जब 1942 में खोज हुई तो भाभा ने 12 से 14 साल में ही बना डाला जबकी अन्य क्षेत्र में भारत विश्व के खोज के मुकाबले उतना जल्दी कर ही नहीं पाया आज भी भारत में थोरियम पर सफलतापूर्वक कार्य चल रहा है और जब ऐ सफल होगा तो भारत खुद ही आत्मनिर्भर हो जायेगा जो भाभा का 3 स्ट्रेज परमाणु कार्यक्रम के अंतर्गत आता है अगर भारत टेक्नोलॉजी में अब्बल नहीं होता तो दो बार परमाणु परीक्षण कैसे कर सकता था जहाँ तक रियक्टर बनाने की बात है तो कम से तीन साल तो बिल्डिंग बनाने में लग जाते हैं जो अन्य उद्योग की बिल्डिंग से अलग होता इसमें भूकंप में भी कुछ ना हो इसका ख्याल रखा जाता और परमाणु ऊर्जा से सम्बंधित काम रेगुलेटरी बोर्ड करता जिसे आईईएफ का गाइडलाइन फॉलो करना पड़ता है उसके बाद मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रुमेंटेशन को इनस्टॉल करना इतना आसान नहीं होता है उसके बाद पार्डिंपिंग और वेलडिंग और उसका टेस्ट करने में ही कम से कम 5 साल लग जाते हैं क्योंकि इसमें जो टैंक बनते हैं वो स्पेशल गुणवत्ता नियम का पालन कर ही बनाए जाते हैं अतः निजी कंपनी के प्रवेश से कितना बनेगा ऐ भविष्य में मालूम हो जायेगा क्योंकि जो आप समझ रहें हैं वो है नहीं कमीशन होते होते कम से 10 से 15 साल लग जायेगा और जैसे जैसे डिले होगा जबरदस्ती तो कर नहीं सकते है क्योंकि इसके कुछ पार्ट्स फ़ौरन से भी आते हैं अतः वहाँ से यहाँ आने में समय लगेगा क्वेश्चन यहाँ ऐ है कि केवल कागजों पर कह कर नहीं हकीकत में जाने की आवश्यकता है जल्दीबाजी की तो क्वालिटी टेस्ट नहीं होगा और ऐसे उपकरण लगे तो रेडीएशन का लीकेज होगा जिसका खामियाजा निर्दोष लोगों को ना जाने कितने सालों तक उठाना होगा विकिरण का रिसाव इसलिए हो सकता है की आप क्वालिटी टेस्ट कम समय में कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि एक दो उपकरण नहीं लगाये जाते हैं बल्कि कम से कम 100 उपकरण तो होते ही हैं अतः ऐ सब या तो प्राइवेट कम्पनी समझ नहीं पा रही या क्रोड मिसअंदरस्टैंडिंग है जो उसे बाद में मालूम होगा और इसकी पढ़ाई भी कड़ी है जो देश में गिने चूने संस्थान में है पहले इसको पढ़ाई करवाये तब ही जब लोगों को इसका फायदा या नुकसान के बारे में पता चलेगा।

राजा की वापसी अकेलेपन, अपमान और आत्मविश्वास से फिर नीली जर्सी तक, अक्षर पटेल उपकप्तान

कांतिलाल मांडोत

भारतीय क्रिकेट में वापसी की कहानियाँ नई नहीं हैं, लेकिन इशान किशन की वापसी साधारण नहीं कही जा सकती। यह सिर्फ एक खिलाड़ी का टीम में लौटना नहीं है, बल्कि उस मानसिक संघर्ष, चुपचाप की गई मेहनत और आत्मसम्मान की जीत की कहानी है, जिसे अक्सर स्पोर्ट्सकॉई नहीं माप सकता। जब चयन समिति ने दो साल बाद इशान किशन का नाम टी20 वर्ल्ड कप टीम में लिया, तो यह फैसला जितना चौंकाने वाला था, उतना ही प्रतीकात्मक भी। यह संदेश था कि क्रिकेट में दरवाजे बंद जरूर होते हैं, लेकिन अगर भीतर आग बाक़ी हो तो वे दोबारा खुल भी सकते हैं।

2023-24 का दौर इशान किशन के करियर का सबसे कठिन समय था। दक्षिण अफ्रीका दौरे से उन्होंने 'मानसिक थकान' का हवाला देकर नाम वापस लिया। उस एक फैसले ने उनके पूरे करियर की दिशा बदल दी। भारतीय क्रिकेट में, जहां निरंतरता और उपलब्धता को सबसे बड़ा गुण माना जाता है,

वहां यह कदम मैनेजमेंट को रास नहीं आया। नतीजा यह हुआ कि वह न सिर्फ टीम से बाहर हो गए, बल्कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी हाथ से चला गया। जिन मैदानों पर कभी उनकी आक्रामक बल्लेबाजी की चर्चा होती थी, वहां अचानक सन्नाटा छा गया। आलोचनाएं शुरू हुईं, सवाल उठे, और यह तक कहा जाने लगा कि इशान किशन का अध्याय अब समाप्त हो चुका है।

लेकिन क्रिकेट सिर्फ आकड़ों और चयन सूचियों का खेल नहीं है, यह धैर्य और आत्मविश्वास की परीक्षा भी है। इशान ने उस दौर में शोर नहीं मचाया। उन्होंने कोई सार्वजनिक सफाई नहीं दी, न ही चयनकर्ताओं पर निशाना साधा। वह बस चुपचाप मैदान पर लौटे, घरेलू क्रिकेट खेला, फिटनेस पर काम किया और सबसे अहम, अपने मन को संभाला। एक इंटरव्यू में उन्होंने फिल्म बाहुबली का डायलॉग याद किया।

राजा जहां भी जाता है, राजा ही रहता है। यह कोई फिल्मी लाइन भर नहीं थी, बल्कि उनके लिए मानसिक संबल बन गई। जब चारों

तरफ से संदेह था, तब यही विश्वास उन्हें आगे बढ़ाता रहा।

इशान किशन को खासियत हमेशा उनकी निडरता रही है। विकेटकीपर-बैटर के तौर पर वह पावरप्ले में मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। भारतीय टीम मैनेजमेंट इस समय ओपीनग में ऐसे विकेटकीपर की तलाश में है, जो बल्लेबाजी में आक्रामक हो और टीम को संयोजन में लचीलापन दे सके। यही वजह है कि शुभमन गिल जैसे स्थापित खिलाड़ी को बाहर रखा गया। यह फैसला फॉर्म से ज्यादा भूमिका से जुड़ा था। इशान इस भूमिका में फिट बैठते हैं। उनके होने से टीम को अतिरिक्त बल्लेबाज या ऑलराउंडर खिलाने की आजादी मिलेगी है, जो टी20 क्रिकेट में निर्णायक साबित हो सकती है।

इशान की वापसी इसलिए भी खास है क्योंकि यह उस दौर में हुई है, जब भारतीय टीम प्रतिभा से ज्यादा विशेष भूमिका पर भरोसा कर रही है। चयन समिति के फैसले साफ संकेत देते हैं कि अब नाम नहीं, जरूरत अहम है।



मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने नाबार्ड के राज्य फोकस पेपर 2026-27 का किया विमोचन

पथ प्रवाह, देहरादून।

उत्तराखंड के समावेशी, संतुलित और सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत 23 दिसंबर 2025 को देहरादून में आयोजित सहकारिता मेला 2025 के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नाबार्ड द्वारा तैयार राज्य फोकस पेपर 2026-27 का विधिवत विमोचन किया। यह दस्तावेज राज्य के प्राथमिकता क्षेत्रों में ऋण प्रवाह को सुदृढ़ करने और ग्रामीण एवं कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण नीति-दस्तावेज माना जा रहा है।

विमोचन कार्यक्रम में माननीय सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत, राज्य सभा सांसद नरेश बंसल, राजपुर विधायक खजान दास, देहरादून नगर निगम के महापौर सौरभ थपलियाल, उत्तराखंड सहकारी समितियों के निबंधक मेहरबान सिंह बिष्ट, नाबार्ड के मुख्य



महाप्रबंधक पंकज यादव सहित बैंकिंग, सहकारिता एवं प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। नाबार्ड द्वारा तैयार यह राज्य फोकस पेपर जिला स्तर पर

तैयार पोर्टेशियल लिंकड क्रेडिट प्लान पर आधारित है, जो वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य की ऋण क्षमता का व्यापक और यथार्थ आकलन प्रस्तुत करता है। दस्तावेज के

अनुसार उत्तराखंड के प्राथमिकता क्षेत्रों के लिए 65,916 करोड़ की अनुमानित ऋण क्षमता निर्धारित की गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 20.50 प्रतिशत अधिक है। यह वृद्धि राज्य की आर्थिक संभावनाओं, उद्यमिता और ग्रामीण विकास के प्रति बढ़ते विश्वास को दर्शाती है।

यह फोकस पेपर कृषि, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME), बुनियादी ढांचा विकास, आजीविका सृजन तथा जलवायु परिवर्तन से संबंधित पहलों जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष जोर देता है। इसके माध्यम से संतुलित कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए एक स्पष्ट और व्यावहारिक रोडमैप प्रस्तुत किया गया है, जिससे रोजगार सृजन, आय वृद्धि और वित्तीय समावेशन को गति मिलेगी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नाबार्ड के इस महत्वपूर्ण प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि राज्य फोकस पेपर उत्तराखंड के विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक

मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में कार्य करेगा। उन्होंने बैंकों, सहकारी संस्थाओं और विभिन्न विभागों से आह्वान किया कि वे इस दस्तावेज को अपनी योजनाओं और कार्यक्रमों में समेकित कर जमीनी स्तर तक लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार नाबार्ड के साथ समन्वय में कृषि, ग्रामीण विकास और उद्यमिता को सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह फोकस पेपर वार्षिक ऋण योजना को अंतिम रूप देने, नीति निर्माण को प्रभावी बनाने और सतत विकास की रणनीतियों को मजबूती प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

कार्यक्रम के दौरान नाबार्ड ने राज्य सरकार को आश्वासन दिया कि वह ऋण योजना, वित्तीय सहयोग और विकासोन्मुख हस्तक्षेपों के माध्यम से उत्तराखंड के समावेशी विकास में अपनी सक्रिय भागीदारी जारी रखेगा।

क्वेस्ट 2025 में डीएवी पब्लिक स्कूल, देहरादून के विद्यार्थियों ने दिलाया गौरव

पथ प्रवाह, देहरादून। शैक्षणिक उत्कृष्टता की सशक्त परंपरा को आगे बढ़ाते हुए डीएवी पब्लिक स्कूल, देहरादून के विद्यार्थियों ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है। दिल्ली पब्लिक स्कूल, गौतम बुद्ध नगर में 20 दिसंबर 2025 को आयोजित प्रतिष्ठित 'क्वेस्ट 2025 - राष्ट्रीय फाइनल' विजय प्रतियोगिता में विद्यालय के छात्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर न केवल विद्यालय, बल्कि पूरे देहरादून क्षेत्र को गौरवान्वित किया।

यह राष्ट्रीय स्तर की ज्ञान-आधारित विजय प्रतियोगिता देश के विभिन्न प्रमुख शहरों—देहरादून, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद, इंदौर, वाराणसी, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, लखनऊ सहित अनेक स्थानों से आए प्रतिभागियों के बीच आयोजित की गई, जहाँ तीव्र प्रतिस्पर्धा



और बौद्धिक चुनौती का माहौल रहा। कड़े मुकाबले के बीच डीएवी पब्लिक

स्कूल, देहरादून के कक्षा 11 'अ' के प्रतिभाशाली छात्र आरव सिन्हा एवं अक्ष यादव

ने अपने गहन ज्ञान, तार्किक क्षमता, त्वरित निर्णय-शक्ति और टीमवर्क का प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर तृतीय स्थान प्राप्त किया। यह उपलब्धि न केवल उनकी व्यक्तिगत मेहनत का परिणाम है, बल्कि विद्यालय की सुदृढ़ शैक्षणिक व्यवस्था और शिक्षकों के सतत मार्गदर्शन का भी प्रमाण है।

इस उल्लेखनीय सफलता पर प्रतियोगिता आयोजकों द्वारा दोनों विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र एवं घड़ी उपहार स्वरूप प्रदान की गई। यह सम्मान उनकी उपलब्धि का प्रतीक होने के साथ-साथ समय के महत्व, अनुशासन और निरंतर परिश्रम का भी संदेश देता है।

विद्यालय परिवार में इस उपलब्धि को लेकर हर्ष और गर्व का वातावरण है। विद्यार्थियों की इस सफलता ने अन्य छात्रों को भी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग

लेने और अपनी प्रतिभा को नए आयाम देने के लिए प्रेरित किया है।

विद्यालय की प्रधानाचार्या श्रीमती शालिनी समाधिया ने आरव सिन्हा एवं अक्ष यादव को इस शानदार उपलब्धि पर हार्दिक बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएँ विद्यार्थियों में ज्ञान-वृद्धि के साथ-साथ तार्किक क्षमता, आत्मविश्वास, नेतृत्व और टीम भावना को सुदृढ़ करती हैं तथा उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करती हैं।

गौरतलब है कि डीएवी पब्लिक स्कूल, देहरादून के इन होनहार विद्यार्थियों की यह सफलता विद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता और निरंतर उत्कृष्टता की दिशा में एक और स्वर्णिम अध्याय जोड़ती है।

एक नजर

सौ मीटर दौड़ में पिकी और आशीष ने मारी बाजी



पथ प्रवाह, हरिद्वार। सांसद खेल महोत्सव के तहत जनपद स्तरीय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ कराते हुए रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने खिलाड़ियों की हैसला अफजाई की। पहले दिन जनपद की 11 विधानसभा स्तर पर विजयी खिलाड़ियों ने जिले स्तर पर प्रतिभाग किया। इस दौरान सभी खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया।

पहले दिन की खेल प्रतियोगिताओं में पिट्टू खेल बालिका वर्ग में फाइनल मुकाबला रानीपुर विधानसभा व खानपुर विधानसभा के मध्य हुआ जिसमें खानपुर की टीम विजयी हुई। म्यूजिकल चेयर में अनुभा-प्रथम (ज्वालापुर विस), वरनिका-द्वितीय (भगवानपुर विस) तथा कुमकुम (हरिद्वार विस) तृतीय रही। 100 मी. दौड़ बालिका वर्ग में पिकी (खानपुर विस) प्रथम, हिमानी (भगवानपुर विस) द्वितीय तथा अंशिका (पिरान कलियर विस) तृतीय रही। दौड़ 100 मी. बालक वर्ग में आशीष (लक्सर विस) प्रथम, अजय कुमार (भगवानपुर विस) द्वितीय तथा अखिल नेगी (हरिद्वार विस)-तृतीय रहे। दौड़ 400 मी. बालिका वर्ग में पिकी (खानपुर विस) प्रथम, अंशिका गुसाई (रानीपुर विस) द्वितीय तथा तन्नु (मंगलौर विस) तृतीय रही। दौड़ 400 मी. बालक वर्ग में यश चौधरी (रुड़की विस) प्रथम, अंशुल (भगवानपुर विस) द्वितीय तथा नितिन पंवार (खानपुर विस) तृतीय रहे। रस्साकसी बालिका वर्ग में फाइनल मुकाबला झबरेड़ा विधानसभा तथा रानीपुर विधानसभा के मध्य हुआ जिसमें झबरेड़ा विधानसभा विजयी रही। वालीबॉल बालिका वर्ग में फाइनल मुकाबला खानपुर और रानीपुर विधानसभा के मध्य हुआ? जिसमें खानपुर विजयी रही। चम्मच दौड़ बालिका वर्ग में रिंतु (हरिद्वार विधानसभा) विजयी रही। चम्मच दौड़ बालक वर्ग में अवि (भगवानपुर विधानसभा) विजयी रहा।

इस अवसर पर रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने खिलाड़ियों से परिचय लेते हुए उनकी हैसला अफजाई की तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। जिलाध्यक्ष भाजपा आशुतोष शर्मा, जिला उपाध्यक्ष लव शर्मा, वरिष्ठ नेता भाजपा विमल कुमार, जिला महामंत्री भाजपा हीरा सिंह बिष्ट, जिला क्रीड़ा अधिकारी शबाली गुरुंग आदि मौजूद रहे।

शगुफता खान के नेतृत्व में महिलाओं ने ली पार्टी की सदस्यता

लक्सर, शौकीन सिद्दीकी।

जन अधिकार पार्टी की वरिष्ठ नेत्री शगुफता खान के नेतृत्व में लोको कालोनी लक्सर में सदस्यता अभियान का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में क्षेत्र की महिलाओं ने बड़-चढ़कर भाग लिया। इस दौरान पार्टी की जनहितकारी विचारधारा, सामाजिक न्याय, समान अधिकार और जनता की आवाज को मजबूती से उठाने के संकल्प से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।

इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि पार्टी बिना किसी भेदभाव के समाज के हर वर्ग—महिला, युवा, मजदूर, किसान और कमजोर तबकों—के अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। यही कारण है कि आज पार्टी की नीतियों और विचारधारा से प्रभावित होकर



लोग स्वेच्छा से पार्टी से जुड़ रहे हैं और संगठन को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। कार्यक्रम में विशेष रूप से जिला प्रभारी हरिद्वार फैजान अंसारी, जिला उपाध्यक्ष मांगा हसन ब्लॉक अध्यक्ष एहसान शाह एवं स्थानीय लोग उपस्थित रहे। पार्टी की सदस्यता ग्रहण

करने वाली महिलाओं में यासमीन, सादिया सोफिया, शाईस्ता, रीका, सोनिया, कहकशा, आलिया, मेहरूबा, सानिया मेहराना किसवर, नूरजहां कमरी, चांदनी साईना, शमा परवीन, उजमा यासमीन, गुलनाज आदि शामिल रही।

जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर निवासरत पात्रों तक पहुंचें: मुकेश कुमार

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को उपलब्ध हो इसके लिए अध्यक्ष (राज्यमंत्री) उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग मुकेश कुमार की अध्यक्षता में जिला सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अंतिम छोर पर निवासरत अनुसूचित जाति व्यक्तियों को सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर हाल में उपलब्ध हो, इसमें किसी भी प्रकार की कोई शिथिलता एवं लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं का प्रचार-प्रसार करने और दूरदराज के गांवों तक लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने योजनाओं की प्रगति, पारदर्शिता और वास्तविक लाभार्थियों तक उनकी पहुंच की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व



में राज्य सरकार अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। इस दिशा में सभी विभागीय अधिकारी जिम्मेदारी से कार्य करें और योजनाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी रूप से लागू करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक विभाग में एक नोडल अधिकारी नामित कर योजनाओं की निरंतर मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही एससी/एसटी छात्र-छात्राओं के लिए संचालित छात्रवृत्ति, छात्रावास, कोचिंग, आर्थिक सहायता

एवं अन्य योजनाओं का लाभ समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिन अधिकारियों के विरुद्ध लापरवाही की शिकायत प्रोत होती है तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। बैठक में अपर जिलाधिकारी पी आर चौहान ने अध्यक्ष को पौधा भेंटकर स्वागत किया। उन्होंने अध्यक्ष को आश्वासन दिया है कि उनके द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि उनका अनुपालन संबंधित विभागों से तत्परता से किया जाएगा।



मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का रानीखेत की धरती से राष्ट्रभक्ति का संदेश

कुमाऊं रेजीमेंट केंद्र में अमर शहीदों को श्रद्धांजलि, सैनिकों व अग्निवीरों का बढ़ाया हौसला

पथ प्रवाह, रानीखेत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुमाऊं रेजीमेंट केंद्र, रानीखेत पहुंचकर राष्ट्र की रक्षा में अपने प्राण न्योछावर करने वाले अमर बलिदानियों को पुष्प चक्र अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उन्होंने वीर सैनिकों और अग्निवीरों से आत्मीय संवाद कर उनके अदम्य साहस, शौर्य और देशभक्ति की भावना को नमन करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने अपने भ्रमण के दौरान कुमाऊं रेजीमेंट केंद्र में संचालित प्रशिक्षण व्यवस्थाओं का विस्तृत अवलोकन किया तथा आधुनिक हथियारों और सैन्य संसाधनों की जानकारी ली। उन्होंने केंद्र में उपलब्ध अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे सशक्त और आधुनिक प्रशिक्षण केंद्र ही भारतीय सेना को विश्व की श्रेष्ठ सेनाओं में अग्रणी बनाए रखते हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने वीर नारियों के कल्याण हेतु संचालित विभिन्न गतिविधियों और योजनाओं का भी अवलोकन किया।

रेजीमेंट मुख्यालय के भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सैन्य



अधिकारियों, सैनिकों तथा उनके परिवारजनों से भी भेंट की और उनका कुशलक्षेम जाना। सैनिकों एवं अग्निवीरों के साथ संवाद करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में भारतीय सेना आज पहले से कहीं अधिक सशक्त, सक्षम और आत्मनिर्भर बनी

है। उन्होंने कहा कि हमारी सेना देश की सीमाओं की रक्षा के लिए हर चुनौती का साहस और पराक्रम के साथ सामना कर रही है तथा दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने में पूरी तरह सक्षम है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने स्पष्ट किया कि उत्तराखंड सरकार पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों तथा अमर बलिदानियों के आश्रितों के



सम्मान और कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। राज्य सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पेंशन एवं आर्थिक सहायता से जुड़ी अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, ताकि वीर परिवारों को हर स्तर पर सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का संबल मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि

देवभूमि उत्तराखंड का सैन्य परंपराओं से गहरा नाता रहा है और यहां का हर परिवार किसी न किसी रूप में देश सेवा से जुड़ा रहा है। प्रदेश सरकार का यह सतत प्रयास है कि सैनिकों और उनके परिवारों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और उन्हें समाज में सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हो।

एक नजर

योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता: रेनू बिष्ट



पथ प्रवाह, पौड़ी। विकासखंड द्वारीखाल की न्याय पंचायत डाबर में स्थित अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज देवीखेत में विधायक रेनू बिष्ट की अध्यक्षता में बहुउद्देश्यीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान 32 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण किया गया। अधिकांश शिकायतें लोक निर्माण विभाग एवं पेयजल निगम से संबंधित रहीं। मंगलवार को देवीखेत में आयोजित शिविर में विधायक ने कहा कि जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार अभियान का मुख्य उद्देश्य जनता की समस्याओं को उनके क्षेत्र में ही सुनकर उनका त्वरित समाधान करना है। उन्होंने कहा कि सरकार निरंतर प्रयासरत है कि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। बहुउद्देश्यीय शिविरों के माध्यम से शासन एवं प्रशासन सीधे जनता से संवाद स्थापित कर रहा है, जिससे समस्याओं का त्वरित निस्तारण संभव हो पा रहा है। भविष्य में भी इस प्रकार के शिविर नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि शिविर का उद्देश्य क्षेत्रीय जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान एवं विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाना रहा। शिविर में आयुष विभाग द्वारा 39 लोगों को आयुर्वेदिक दवा वितरित व परामर्श, स्वास्थ्य विभाग द्वारा 23 लोगों को दवा वितरण व परामर्श, पशुपालन विभाग द्वारा 18 लाभार्थियों को दवा वितरित व पशु चिकित्सीय परामर्श, उद्योग विभाग द्वारा 12 लाभार्थियों को योजनाओं की जानकारी प्रदान की गयी, जबकि 16 लोगों को बैंकर्स द्वारा वित्तीय परामर्श दिया गया। इसके अलावा बाल विकास, पशुपालन, स्वास्थ्य विभाग, उद्योग विभाग, बैंकर्स, कृषि विभाग, सहकारिता, सेवायोजन विभाग, डेयरी विभाग एवं विद्युत विभाग द्वारा विभागीय स्टॉल लगाकर स्थानीय जनता को सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गयी तथा पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। शिविर में जिला पंचायत सदस्य सुराड़ी अर्जुन सिंह, ग्राम प्रधान डाबर सुरेश ममगाई, एसडीओ वन अनामिका सिंह, अधिशासी अभियंता लोनिवि लैंसडौन विवेक कुमार, दुगड्डा निर्भय सिंह, अधिशासी अभियंता सिंचाई अनिल राठौर, अधिशासी अभियंता जल निगम आशीष मिश्रा, जयपाल सिंह बिष्ट सहित क्षेत्र के अनेक लाभार्थी एवं ग्रामीण उपस्थित रहे।

पर्यटन विभाग की नाकामी, बड़ेथ गांव के युवाओं ने किया ये सराहनीय काम

पथ प्रवाह, पाबौ। जनपद पौड़ी गढ़वाल के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल ताराकुंड की ओर जाने वाले मार्ग पर लंबे समय से संकेतक बोर्डों की कमी के कारण राहगीरों और श्रद्धालुओं को अब परेशान नहीं होना पड़ेगा। स्थानीय युवाओं ने इस समस्या का समाधान करने के लिए खुद ही प्रयास किये और जगह जगह साइन बोर्ड लगाकर श्रद्धालुओं को राहत प्रदान की। पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी होने के बावजूद कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के विभाग द्वारा इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की गई। विभागीय उदासीनता के चलते कई बार श्रद्धालु रास्ता भटक जाते थे। इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए बड़ेथ गांव के जागरूक युवाओं ने स्वयं पहल करते हुए ताराकुंड जाने वाले मार्ग पर जगह-जगह साइन बोर्ड लगवाए। इन साइन बोर्डों पर स्पष्ट दिशा-निर्देश, दूरी की जानकारी और महत्वपूर्ण स्थलों का उल्लेख किया गया है, जिससे अब राहगीरों और श्रद्धालुओं को बिना किसी असमंजस के अपने गंतव्य तक पहुंचने में सुविधा होगी। युवाओं की इस सराहनीय पहल से न केवल यात्रियों को राहत मिली है, बल्कि क्षेत्र में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

देवलगढ़ में लगे बहुउद्देश्यीय शिविर में दिखी सहभागिता, 23 विभागों ने लगाए स्टॉल

पथ प्रवाह, पौड़ी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में संचालित जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार कार्यक्रम के तहत मंगलवार को विकासखंड खिसू की न्याय पंचायत देवलगढ़ में बहुउद्देश्यीय शिविर आयोजित किया गया। शिविर की अध्यक्षता प्रभारी जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत ने की। शिविर में 276 लाभार्थियों को योजनाओं से लाभान्वित किया गया।

शिविर में प्रभारी जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविर में आने वाले पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही उन्हें योजनाओं से लाभान्वित भी किया जाए। बहुउद्देश्यीय शिविर के दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनीं। शिविर में कुल 30 शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। प्रभारी जिलाधिकारी ने शेष शिकायतों के शीघ्र समाधान के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए। शिविर में अधिकतर शिकायतें जल संस्थान, विद्युत विभाग, लोक निर्माण विभाग और वन विभाग से रहीं।

प्रभारी जिलाधिकारी गिरीश गुणवंत ने कहा कि जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याओं का समाधान उनके द्वार पर जाकर किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यह अभियान 18 दिसंबर से शुरू होकर आगामी 18 मार्च तक जनपद की सभी 115 न्याय पंचायतों में संचालित किया जाएगा, जिससे आमजन को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके। शिविर में समाज कल्याण, स्वास्थ्य,



पशुपालन, कृषि, आयुर्वेदिक एवं यूनानी, वन, होम्योपैथिक, उद्यान, खाद्य पूर्ति विभाग सहित कुल 23 विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए। सैनिक कल्याण विभाग ने सात पूर्व सैनिकों को केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। उद्यान विभाग द्वारा 10 लाभार्थियों को योजनाओं की जानकारी दी गयी तथा तीन लोगों को यंत्र वितरण और 10 लाभार्थियों को कीटनाशक व खाद वितरित की गयी।

स्वास्थ्य जांच और दवा की वितरित

आयुर्वेदिक विभाग ने 80 लोगों की स्वास्थ्य जांच कर 68 को दवाइयां वितरित कीं। बाल विकास विभाग ने दो लाभार्थियों को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट, दो गोद भराई और दो अन्नप्राशन कराए तथा 15 लोगों को योजनाओं की जानकारी दी। पशुपालन विभाग द्वारा 09 पशुपालकों को पशुओं की दवाइयां दी और 13 लोगों को विभागीय योजनाओं से अवगत कराया गया। कृषि विभाग ने 12 लाभार्थियों को कृषि यंत्र तथा 04 को कृषि से

संबंधित दवाइयां वितरित कीं। राजस्व विभाग ने मौके पर ही 04 शिकायतों का निस्तारण किया। रेशम विभाग द्वारा 12 लोगों को योजनाओं की जानकारी दी गई, जबकि स्वास्थ्य विभाग ने 27 लोगों को दवाइयां वितरित कीं। होम्योपैथिक विभाग ने 48 लोगों को सामान्य बीमारियों के संबंध में परामर्श दिया।

ये रहे मुख्य रूप से उपस्थित

इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख खिसू अनिल भंडारी, ज्येष्ठ प्रमुख नितिन रावत, ग्राम प्रधान देवलगढ़ सुमन देवी, उपजिलाधिकारी नूपुर वर्मा, जिला कार्यक्रम अधिकारी देवेन्द्र थपलियाल, मत्स्य अधिकारी अभिषेक मिश्रा, सहायक निदेशक दुग्ध नरेंद्र लाल, तहसीलदार दीपक भंडारी, सहायक समाज कल्याण अधिकारी पंकज मैदोली, सहायक सैनिक कल्याण अधिकारी सत्यपाल सिंह रावत, सहायक निबंधक सहकारिता पान सिंह राणा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी और स्थानीय लोग उपस्थित रहे।

मानव-वन्यजीव संघर्ष पर वन अधिकारियों ने ग्रामीणों को किया जागरूक

पथ प्रवाह, पाबौ। पाबौ क्षेत्र की वन पंचायत पसीणा व पाबौ में वनाग्नि की बढ़ती घटनाओं और मानव-वन्यजीव संघर्ष को लेकर वनाग्नि सुरक्षा एवं जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी की अध्यक्षता वन सरपंच मुरेन्द्र सिंह ने की, जिसमें वन पंचायत पसीणा के ग्रामीणों के साथ-साथ वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य ग्रीष्मकाल में जंगलों में लगने वाली आग की रोकथाम और गांवों के आसपास बढ़ती वन्यजीव गतिविधियों से उत्पन्न खतरे के प्रति ग्रामीणों को सतर्क करना रहा। गोष्ठी के दौरान ग्रामीणों ने बताया गांव के आसपास वन्यजीवों की आवाजही देखी गई है, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। इस पर ग्रामीणों ने मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए वन पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत झाड़ियों, विशेषकर लेटाना (लैंटाना) की कटाई की आवश्यकता पर जोर दिया। वन दरोगा सतीश



लाल शाह ने ग्रामीणों को वनाग्नि से होने वाले गंभीर नुकसान के बारे में विस्तार से जानकारी दी। गोष्ठी में विभागीय कर्मचारियों द्वारा वन्यजीवों से सुरक्षा के विभिन्न उपाय, सतर्कता के तरीके और आपसी समन्वय से समस्या के समाधान पर भी चर्चा की गई। अंत में वन

पंचायत सरपंच द्वारा सभी ग्रामीणों से वन एवं वन्यजीव संरक्षण में सहयोग की अपील की गई। बैठक में उपस्थित सभी ग्रामीणों और वन कर्मचारियों ने वनाग्नि रोकथाम एवं मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए सामूहिक प्रयास करने का संकल्प लिया।

जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की निगरानी में परवान चढ़ रहा सफाई अभियान

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

तीर्थनगरी हरिद्वार को स्वच्छ, सुंदर, क्लीन जनपद बनाने के लिए सफाई अभियान मंगलवार को भी जारी रहा। सफाई अभियान नगरीय क्षेत्र से लेकर गांव कस्बों एवं सड़क मार्गों तक निरन्तर चलाया जा रहा है। जनपद हरिद्वार को स्वच्छ, सुंदर बनाने के लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित प्रयासरत हैं। इसी लिए वह सफाई अभियान की स्वयं निरन्तर मॉनिटरिंग कर रहे हैं।

नगर मजिस्ट्रेट कुशम चौहान ने अवगत कराया है कि नगर निगम की टीम द्वारा आज ऋषिकुल से प्रेम नगर पुल के बीच कांवड़ पटरी एवं आसपास के क्षेत्र में सघन सफाई अभियान चलाया गया तथा नगर निगम को



निरंतर सफाई अभियान जारी रखने के निर्देश दिए। अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत संजय खंडूरी ने अवगत कराया है कि पृथ्वीराज चौहान चौक बहादुराबाद

क्षेत्रांतर्गत जिला पंचायत द्वारा साफ सफाई एवं पालीथीन,प्लास्टिक अवशिष्ट एकत्रित करने की कार्यवाही की जा रही है। बीएचईएल नगर प्रशासक संजय पवार ने

अवगत कराया है कि टिहरी विस्थापित कॉलोनी मार्ग एवं कॉलोनी में सफाई अभियान चलाया गया।

जिला पशु चिकित्सा अधिकारी दी के चंद ने अवगत कराया है कि राजकुलिया पशु चित्रालय बहादुराबाद , उप चिकित्सालय नारसन,उप चिकित्सालय रायसी,उप चिकित्सालय सिकरौड़ा क्षेत्रांतर्गत सफाई अभियान चलाया गया। सहायक परियोजना निदेशक नलिनीत थिलडियाल ने अवगत कराया है कि ग्राम पंचायत कुरड़ी ब्लॉक नारसन में पंचायत भवन में महिला समूह द्वारा साफ सफाई का कार्य किया गया। खंड विकास अधिकारी खानपुर ने अवगत कराया है कि प्रहलादपुर,चंद्रपुरी खादर खण्ड खानपुर क्षेत्रांतर्गत में साफ सफाई अभियान

चलाया गया। खंड विकास अधिकारी रुड़की द्वारा अवगत कराया है कि रुड़की क्षेत्रांतर्गत सफाई का कार्य कराया गया। खंड विकास अधिकारी बहादुराबाद ने अवगत कराया है कि मोहम्मदपुर कुन्हारी क्षेत्रांतर्गत साफ सफाई का कार्य किया गया। खंड विकास अधिकारी नारसन ने अवगत कराया है कि ग्राम पंचायत टांडाबेनेडा विकास खंड नारसन क्षेत्रांतर्गत नालियों की सफाई के साथ सड़क किनारे पड़े गोबर को भी हटाया गया। खंड विकास अधिकारी लक्सर ने अवगत कराया है कि भोगपुर लक्सर साफ सफाई अभियान चलाया गया। सिडकुल आर एम कमल किशोर ने अवगत कराया है कि रावली महदूद क्षेत्रांतर्गत साफ सफाई अभियान चलाया गया।

गैडी खाता में लगे बहुउद्देशीय शिविर में पूर्व मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने सुनी जनता की समस्याएं

विकास खण्ड बहादुराबाद और भगवानपुर की न्याय पंचायतों में आयोजित हुए बहुउद्देशीय शिविर

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

जनता की समस्याओं को उनके द्वार पर सुलझाने और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से मंगलवार को लालबाग क्षेत्र के गैडीखाता स्थित शहीद मनोज सिंह चौहान राजकीय इंटर कॉलेज में ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ बहुउद्देशीय शिविर का भव्य आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी डॉ. ललित नारायण मिश्र एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने की।

बहादुराबाद विकासखंड के लालबाग क्षेत्र में ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ शिविर में 225 लाभार्थियों को विभिन्न प्रमाण पत्र वितरित किए गए तथा 987 लोगों को विभिन्न विभागों की संचालित योजनाओं से लाभान्वित किया गया। विकासखंड बहादुराबाद के अंतर्गत आयोजित इस शिविर में 23 सरकारी विभागों ने अपने स्टाल लगाकर जनता की मदद की। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मौके पर ही लोगों के स्वास्थ्य की जाँच की गई, जबकि आधार कार्ड केंद्र पर त्रुटियों का संशोधन किया गया। कृषि विभाग ने बीज वितरित किए और पशुपालन विभाग द्वारा पशुओं के लिए निःशुल्क दवाइयां दी गईं। खाद्य विभाग ने राशन कार्ड से संबंधित समस्याओं का समाधान किया। विशेष रूप से



ग्रामोत्थान (रीप) परियोजना और एनआरएलएम के स्टाल पर स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित स्थानीय उत्पादों का प्रदर्शन और बिक्री की गई।

त्वरित न्याय और स्वच्छता का संकल्प

शिविर के दौरान 70 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 32 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष शिकायतों के लिए मुख्य विकास अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए। शिविर में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा उपस्थित जनता, लाभार्थियों और अधिकारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। उन्होंने अपील की कि जनपद को सुंदर

बनाने के लिए हर नागरिक को स्वच्छता के प्रति जागरूक होना होगा। इस अवसर पर उप प्रमुख धर्मेन्द्र प्रधान, ग्राम प्रधान गाजीवाली देवेन्द्र नेगी, प्रधान पीलीपड़ाव शीशपाल, प्रधान गैडीखाता बिस्मिला, क्षेत्र पंचायत सदस्य पार्वती देवी, नंद किशोर सहित संबंधित अधिकारी एवं क्षेत्रीय जनता मौजूद रही।

भगवानपुर में 192 को मिले प्रमाण पत्र

विकासखंड भगवानपुर की न्याय पंचायत हबीबपुर निवादा, ग्राम वहाबपुर छंगामाजरी में ‘जन-जन की सरकार जन-जन के द्वार’ अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें 192 लोगों को विभिन्न विभागों से प्रमाण पत्र निर्गत किए गए तथा



478 लोगों विभिन्न विभागों की संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया गया। इस शिविर में 812 लोगों ने प्रतिभाग किया।

बहुउद्देशीय शिविर में कुल 61 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 34 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि शेष शिकायतों के निस्तारण हेतु संबंधित विभागों को आवश्यक आदेश जारी कर दिए गए। शिविर में ग्राम वहाबपुर छंगामाजरी सहित न्याय पंचायत के ग्राम से भारी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे, जिससे कार्यक्रम की व्यापक जनभागीदारी स्पष्ट रूप से दिखाई दी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में अध्यक्ष जिला पंचायत किरण चौधरी एवं

अन्य अन्य गणमान्य व्यक्ति पूर्व राज्य मंत्री वीरेंद्र सैनी, अभिषेक राकेश, विधायक प्रतिनिधित्व के रूप में उपस्थित रहे तथा मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र सैनी, मंडल अध्यक्ष विराट गोयल, मंडल अध्यक्ष शादी राम उपस्थित रहे। शिविर की अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी दीपेंद्र नेगी के द्वारा की गई और शिविर में खंड विकास अधिकारी आलोक, ग्राम विकास अधिकारी कुलदीप सैनी, सलामत अली, योगेश एवं राजेंद्र तथा ग्राम पंचायत अधिकारी अनुराग चौहान, ग्राम प्रधान करण पाल सिंह सहित समस्त न्याय पंचायतों के ग्राम प्रधान उपस्थित रहे। कार्यक्रम में लगभग 23 विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

बाल भिक्षावृत्ति व बालश्रम पर सख्त प्रहार, ऋषिकेश से 3 बच्चे रेस्क्यू



पथ प्रवाह, देहरादून

जनपद देहरादून में बाल भिक्षावृत्ति एवं बालश्रम के विरुद्ध जिला प्रशासन का अभियान लगातार सख्ती के साथ जारी है। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशों के क्रम में प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत ऋषिकेश क्षेत्र से भिक्षावृत्ति में लिप्त तीन बच्चों को रेस्क्यू किया गया।

इस संयुक्त कार्रवाई में जिला टास्क फोर्स, श्रम विभाग के लेबर इंस्पेक्टर, एंटी ह्यूमन ट्रेफिकिंग यूनिट तथा चाइल्डलाइन ऋषिकेश की टीम शामिल रही। रेस्क्यू के उपरांत विधिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए एक बालिका को बालिका निकेतन तथा दो बच्चों को शिशु सदन में सुरक्षित रूप से आवसित किया गया है, जहां उनके संरक्षण, देखभाल और पुनर्वास की समुचित व्यवस्था की गई है। जिला

प्रशासन द्वारा बाल भिक्षावृत्ति और बालश्रम के पूर्ण उन्मूलन के उद्देश्य से जनपद स्तर पर नियमित निगरानी एवं रेस्क्यू अभियान संचालित किया जा रहा है। रेस्क्यू किए गए बच्चों के मानसिक एवं सामाजिक पुनर्वास (माइंड रिफॉर्म) हेतु उन्हें आधुनिक इंटरैक्टिव केयर सेंटर में योग, संगीत, खेलकूद एवं रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है, ताकि उन्हें शिक्षा की मुख्यधारा में लाया जा सके। प्रशासन की इस पहल के अंतर्गत अब तक 100 से अधिक बच्चों को बाल भिक्षावृत्ति व बालश्रम से मुक्त कराकर विद्यालयों में प्रवेश दिलाया जा चुका है। जिलाधिकारी ने आमजन से अपील की है कि कहीं भी बाल भिक्षावृत्ति या बालश्रम की जानकारी मिलने पर तत्काल संबंधित विभागों अथवा चाइल्डलाइन को सूचित करें, ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित किया जा सके।

जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार बना ग्रामीण सशक्तिकरण का मॉडल

एक सप्ताह में 93 शिविरों से लाखों ग्रामीणों को राहत

पथ प्रवाह, देहरादून

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर संचालित ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ अभियान ने न्याय पंचायत स्तर पर शासन-प्रशासन को सीधे ग्रामीणों के द्वार तक पहुँचाकर जनसेवा की एक प्रभावी और भरोसेमंद मिसाल कायम की है। इस अभिनव पहल के तहत केवल एक सप्ताह के भीतर प्रदेश भर में 93 बहुउद्देश्यीय शिविर आयोजित किए गए, जिनमें 6,396 शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया गया, जबकि 28,959 ग्रामीणों को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ मिला। साथ ही पारदर्शी और सुगम प्रशासन की दिशा में 9,061 प्रमाणपत्र भी मौके पर ही निर्गत किए गए। मुख्यमंत्री श्री धामी इस अभियान के माध्यम से न्याय पंचायत स्तर पर ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने और पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं की सीधी पहुँच बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध नजर आए। उन्होंने न केवल अभियान की नियमित समीक्षा की, बल्कि स्वयं शिविरों में पहुँचकर ग्रामीणों से संवाद भी किया। मंगलवार को मुख्यमंत्री ने अल्मोड़ा जिले के रानीखेत क्षेत्र में ग्रामीणों से सीधे फीडबैक लिया और विकासखंड ताड़ीखेत की न्याय पंचायत जैनेली में आयोजित बहुउद्देश्यीय शिविर का औचक निरीक्षण किया। इस



दौरान उन्होंने आमजन की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को शिकायतों के त्वरित एवं समयबद्ध निस्तारण के स्पष्ट निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अभियान ग्रामीण जनता के लिए शासन-प्रशासन के दरवाजे खोलने जैसा है, जिससे लोगों को अब अपनी समस्याओं के समाधान के लिए दूर-दराज के कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उन्होंने बताया कि 17 दिसंबर से प्रारंभ हुआ यह अभियान लगभग डेढ़ माह तक संचालित किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक ग्रामीणों को योजनाओं और सेवाओं का लाभ उनके क्षेत्र में ही मिल सके। मुख्यमंत्री श्री धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविरों में आने वाले प्रत्येक पात्र व्यक्ति को सरकारी योजनाओं की संपूर्ण जानकारी और लाभ

पूरी तत्परता से उपलब्ध कराया जाए। साथ ही उन्होंने ग्रामीणों से इन शिविरों का अधिकधिक लाभ उठाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रीगणों और वरिष्ठ अधिकारियों को भी इस जनसेवा अभियान में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को प्रदेश की 10 न्याय पंचायतों में आयोजित शिविरों में 1,572 शिकायतों का समाधान किया गया, 6,563 लोगों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया गया और 2,446 प्रमाणपत्र वितरित किए गए। इसी क्रम में कैबिनेट मंत्री श्री सतपाल महाराज ने भी पिथौरागढ़ जिले के मोस्टामानू मेला स्थल पर आयोजित बहुउद्देश्यीय शिविर में प्रतिभाग कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं और मौके पर ही समाधान के निर्देश दिए।

ओलंपिक की लॉन्चिंग पैड बनेगी मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी: रेखा आर्या

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी के माध्यम से प्रदेश के होनहार खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा को आगे लाने का मौका मिलेगा। यह ट्रॉफी ओलंपिक की लॉन्चिंग पैड बनेगी। खिलाड़ियों को लक्ष्य निर्धारित कर प्रतिभाग करना चाहिए। ऐसा करने से चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक सकता। हरिद्वार के योगस्थली खेल परिसर में मुख्यमंत्री चैंपियंस ट्रॉफी का मंगलवार को जोशीला आगाज हुआ। न्याय पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक चार लेवल पर आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में लगभग 2 लाख खिलाड़ी शिरकत करेंगे। योगस्थली खेल परिसर में खेल मंत्री रेखा आर्या ने ट्रॉफी का ध्वजारोहण और मशाल को प्रज्वलित करके प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। खेल महाकुंभ को इस साल नए प्रारूप में मुख्यमंत्री चैंपियंस ट्रॉफी 2025-26 के रूप में आयोजित किया जा रहा है। प्रतियोगिता न्याय पंचायत, विधानसभा क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र और राज्य स्तरीय चार चरणों में आयोजित की जा रही है।

उद्घाटन अवसर पर खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि इस बार कुल 26 खेल स्पर्धाएं रखी गई हैं, जिनमें आधुनिक खेलों के साथ



परंपरागत खेलों को भी शामिल किया गया है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि सांसद ट्रॉफी जीतने वाली टीम को 2 लाख और विधानसभा ट्रॉफी जीतने वाली टीम को 1 लाख रुपये की नगद पुरस्कार राशि मिलेगी। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि भाजपा सरकार ने खिलाड़ियों के हित के लिए नीतिगत फैसले किए जिनमें बाद राज्य में खेलों को लेकर माहौल बदला और एक खेल संस्कृति विकसित होनी शुरू हुई। उन्होंने कहा कि इस चैंपियनशिप के विजेता भी सरकारी नौकरियों में चार प्रतिशत आरक्षण के हकदार होंगे। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा

कि युवा खेलों को टाइम पास के रूप में नहीं बल्कि करियर के रूप में अपनाएं। अगर वें 100% अनुशासन और समर्पण खेल को देंगे तो उन्हें चैंपियन बनने से कोई रोक नहीं सकता।

नेशनल रिकॉर्ड तोड़ने पर मिलेंगे एक लाख

राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने वाले खिलाड़ियों के लिए 1 लाख रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि घोषित की गई है। प्रतियोगिता के दौरान जीते गए पदकों के आधार पर अंकों का योग करके समग्र चैंपियन का चयन किया जाएगा। चैंपियन चुने गए खिलाड़ी को मुख्यमंत्री ट्रॉफी



और 75 लाख की धनराशि दी जाएगी।

मंत्री संग फोटो के लिए मची होड़

कार्यक्रम समाप्त होने के बाद भी काफी देर तक खेल मंत्री रेखा आर्या आयोजन स्थल पर ही रुकी रही क्योंकि हजारों खिलाड़ी उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहते थे।

मंत्री ने भी उन्हें निराश नहीं किया और खिलाड़ियों के बीच उन्होंने लगभग 1 घंटे का समय गुजारा। इस दौरान उन्होंने सैकड़ों खिलाड़ियों से अलग-अलग बातचीत करके उनका उत्साह बढ़ाया और खिलाड़ियों को भी मंत्री के साथ सेल्फी लेने का पर्याप्त अवसर

मिला।

विधायक आदेश चौहान भी रहे मौजूद

इस अवसर पर विधायक आदेश चौहान, भाजपा जिला अध्यक्ष आशुतोष शर्मा, विमल कुमार, महामंत्री हीरा सिंह बिष्ट, विशेष प्रमुख खेल सचिव अमित सिन्हा, खेल निदेशक आशीष चौहान, अपर निदेशक अजय अग्रवाल, शक्ति सिंह, जिला खेल अधिकारी शबाली गुरुंग, जिला युवा कल्याण अधिकारी प्रमोद पांडे, लव शर्मा, बिंदुपाल, नकलीरण सैनी, तरुण नैय्यर, विनीत जोली, अभिनव चौहान, नितिन चौहान, मनोज सिंह, वीरेंद्र पाल आदि उपस्थित रहे।

सहकारिता मेला 2025 का भव्य शुभारंभ, उत्तराखंड देश का मॉडल राज्य

पथ प्रवाह, देहरादून।

सहकारिता केवल आर्थिक व्यवस्था नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन और आत्मनिर्भरता का सशक्त माध्यम है—इस संदेश के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रेंजर्स ग्राउंड, देहरादून में आयोजित सहकारिता मेला 2025 का भव्य उद्घाटन किया। यह आयोजन अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 एवं उत्तराखंड राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया, जिसमें सहकारिता की शक्ति, तकनीक और पारदर्शिता का प्रभावशाली प्रदर्शन देखने को मिला।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने अपने संबोधन में कहा कि सहकारिता मेला केवल उत्पादों या योजनाओं का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यह उत्तराखंड की ग्रामीण आत्मनिर्भरता, सामाजिक एकजुटता और आत्मसम्मान का जीवंत प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सहकारिता भारतीय संस्कृति का मूल संस्कार है, जहां व्यक्ति अपने निजी हित से ऊपर उठकर समाज के सामूहिक कल्याण के लिए कार्य करता है।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि आज के प्रतिस्पर्धी और वैश्विक युग में सहकारिता की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। इसी महत्व को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2025 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 'सहकार से समृद्धि'



के संकल्प को साकार करने के लिए देश में अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन एक ऐतिहासिक निर्णय रहा है, जिसे केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि उत्तराखंड आज सहकारिता सुधारों में देश का अग्रणी और मॉडल राज्य बन चुका है। उन्होंने बताया कि देश में बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण की शुरुआत उत्तराखंड से हुई और आज प्रदेश की सभी 670 सहकारी समितियां पूरी तरह डिजिटल हो

चुकी हैं। जहां पहले किसान दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर था, वहीं आज वह मोबाइल फोन के माध्यम से सभी सेवाओं से जुड़ रहा है। उन्होंने इसे कांग्रेस के 'कागजी मॉडल' और भाजपा के 'जमीनी मॉडल' का स्पष्ट अंतर बताया।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि सहकारी समितियां अब केवल ऋण वितरण तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती दवाइयां, कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में बीमा, पेंशन, बिजली बिल, आधार और अन्य डिजिटल सेवाएं भी उपलब्ध करा

रही हैं। जो संस्थाएं कभी बोझ समझी जाती थीं, वे आज जनता के लिए सुविधा और विश्वास के केंद्र बन चुकी हैं।

पारदर्शिता पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि सहकारी समितियों का संपूर्ण डेटा राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पर अपलोड किया गया है, जिससे व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हुई है। उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के तहत किसानों, महिला स्वयं सहायता समूहों और सहकारी संस्थाओं को ब्याजमुक्त ऋण देकर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। सहकारी बैंकों में जमा हो रही हजारों करोड़ रुपये की पूंजी जनता के बढ़ते विश्वास का प्रमाण है।

महिला सशक्तिकरण को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सहकारिता समितियों और स्वयं सहायता समूहों को विशेष सहयोग दिया जा रहा है। 'लखपति दीदी' अभियान के माध्यम से लाखों महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं और अपने परिवार व समाज को आर्थिक मजबूती दे रही हैं।

उन्होंने कहा कि जहां कांग्रेस ने महिलाओं को केवल नारे दिए, वहीं भाजपा सरकार ने उन्हें अवसर और संसाधन प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विकास के साथ-साथ उत्तराखंड की पहचान, संस्कृति और सामाजिक ताने-बाने की रक्षा के लिए भी

पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अवैध कब्जों, लैंड जिहाद और अवैध संरचनाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। अवैध मदरसों पर कार्रवाई, ऑपरेशन कालनेमि और समान नागरिक संहिता सरकार की मजबूत इच्छाशक्ति के उदाहरण हैं।

युवाओं के भविष्य पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नकल विरोधी कानून लागू कर भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी बनाया गया है, जिससे हजारों युवाओं को बिना पच्ची-बिना खर्ची सरकारी नौकरी मिली है। उन्होंने कहा कि जहां पहले नौकरियां बिकती थीं, वहीं आज योग्यता ही अवसर का आधार है।

भ्रष्टाचार पर सरकार की नीति स्पष्ट करते हुए मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि जीरो टॉलरेंस के तहत किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह अधिकारी हो या कर्मचारी।

मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि सहकारिता मेला 2025 आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की दिशा में एक जनआंदोलन का रूप लेगा और प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित करने के सरकार के 'विकल्प रहित संकल्प' को नई मजबूती प्रदान करेगा।

कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, विधायक खजान दास, सविता कपूर, सहकारिता विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

जिलाधिकारी आकांक्षा कोण्डे ने स्वस्थ बागेश्वर की दिशा में की सख्त प्रशासनिक पहल

मातृ-शिशु स्वास्थ्य से लेकर झोलाछापों पर कार्रवाई तक जिलाधिकारी के सख्त निर्देश

पथ प्रवाह, बागेश्वर

जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़, प्रभावी व जनोन्मुखी बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी आकांक्षा कोण्डे ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की व्यापक समीक्षा बैठक ली। बैठक में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, जन औषधि केंद्रों की स्थिति, दिव्यांगजन कल्याण योजनाएं तथा विभिन्न राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की बिंदुवार और गहन समीक्षा की गई। जिलाधिकारी आकांक्षा कोण्डे ने गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए ऐसे क्षेत्रों (पॉइंट्स) की पहचान करने के निर्देश दिए, जहां पंजीकरण की स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर है। उन्होंने शत-प्रतिशत एएनसी



(एंटीनेटल केयर) सुनिश्चित करने पर विशेष बल देते हुए कहा कि गर्भावस्था के दौरान समय पर जांच और देखभाल मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने में अहम भूमिका निभाती है।



इसके साथ ही उन्होंने उच्च जोखिम गर्भावस्था (हाई रिस्क प्रेग्नेंसी) के मामलों की एसीएमओ स्तर पर नियमित, प्रभावी एवं निगरानी आधारित समीक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने पिछले पांच वर्षों में जनपद में हुए स्किल्ड बर्थ (प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा कराए गए प्रसव) तथा उनसे संबंधित मृत्यु के आंकड़े प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने

संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए निरंतर जागरूकता, बेहतर सुविधाएं और प्रभावी मॉनिटरिंग पर जोर देते हुए कहा कि सुरक्षित प्रसव ही स्वस्थ समाज की नींव है। स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को झोलाछाप डॉक्टरों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने तथा पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अवैध और अनधिकृत चिकित्सा गतिविधियों पर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने आगामी एक माह के भीतर जनपद के सभी जन औषधि केंद्रों को पूर्ण रूप से क्रियाशील कराने के निर्देश दिए, ताकि आमजन को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयों की सुविधा सुनिश्चित हो सके।